01/2013

सप्रू हाउस लेख

रणनीति और समझौतों के प्रति चीन का बदलता दृष्टिकोण : पहलेवअब

अशोक कपूर

विश्व मामलों की भारतीय परिषद्
सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड़, नई दिल्ली-110001

रणनीति और समझौतों के प्रति चीन का बदलता दृष्टिकोणः पहले व अब

अशोक कपूर

रणनीति और समझौतों के प्रति चीन का बदलता दृष्टिकोणः पहले व अब

प्रथम प्रकाशित, 2013
कॉपीराइट ©विश्व मामलों की भारतीय परिषद्
आईएसबीएनः 978-81-926825-7-0

सभी अधिकार संरक्षित हैं। इस प्रकाशन के किसी भी भाग को कॉपीराइट मालिक से अनुमति के बगैर पुनरुत्पादित, पुनःप्राप्ति प्रणाली में भंडारित, अथवा किसी भी प्ररूप में चाहे इलैक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी से रिकार्डिंग अथवा अन्यथा, रूपांतरित नही किया जा सकता है।

इस प्रकाशन में व्यक्त किये गये तथ्य एवं मतों की जिम्मेदारी पूर्णतया लेखक के पास सुरक्षित है तथा उसका विवेचन आवश्यक रूप से विश्व मामलों की भारतीय परिषद्, नई दिल्ली के विचारों को व्यक्त नहीं करती है।

विश्व मामलों की भारतीय परिषद्
सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड़, नई दिल्ली- 110 001, भारत
टेलीफोन : +91-11-23317242, फैक्स: +91-11-23322710

www.icwa.in

विषयवस्तु

1.	सार	5
2.	परिचय	7
3.	चीन का कारक रणनीतिक चुनौतियों के साथ विश्व इतिहास के महत्व में उत्पन्न हुआ है	8
4.	चीन के राजनयिक विकास विभिन्न स्तरों के माध्यम से विकसित हुए हैं	9
5.	चीन के विदेश संबंधों में गतिशीलता का स्थायी महत्व	19
6.	चीन की शासनकला में कूटनीति की भूमिका तथा नियंत्रित वृद्धि और युद्ध की तैयारी की भविष्य की संभावना: 21वीं सदी में चीन 24	24
7.	चीन की समझौतों की रणनीतियां और अभिप्रेत उत्तराधिकारी और अनभिप्रेत स्थितियां 28	28
8.	चीन की बातचीत की कार्यनीति का श्रंखला समूह	38
9.	नव चीन की कूटनीतिः “नदी पार करने के लिए 44 कंकंड पत्थरों के आस-पास तैयारी करना”?	44
10.	समाप्ति टिप्पणी	52

रणनीति और समझौतों के प्रति चीन का बदलता दृष्टिकोणः पहले व अब

सार

गैर-चीनी विश्व के साथ चीन के वार्तालापों के अनुभव- 1800 के दशक में ब्रिटेन, 50 के दशक में कोरिया में, 50 के दशक के मध्य में भारत-चीन में, 40 और 70 के दशक में अमेरिका में तथा 1949 से अब तक भारत में- के दशक में - मुख्य रणनीतिक सिद्धांतों की प्रधानता को दर्शाता है जो दुनिया के विषय में चीन के दृष्टिकोण और उसमें इसकी स्थिति, भूराजनीतिक संदर्भ में उसके प्रतिद्वंद्वियों की स्थिति के बारे में उसके दृष्टिकोण में अंतर्निहित हैं। चीन का दृष्टिकोण बाहरी वातावरण पर लगातार ध्यान देता है लेकिन उसकी कूटनीतिक शैली बदलती रहती है। जब यह बेसहारों पर शासन कर सकता था, उस समय इसने मध्य साम्राज्य की स्थिति को अपनाया। 19वी सदी में जब यह रूस, ब्रिटेन और तिब्बत शक्तियों के संपर्क में आया तो यह बाहरी खतरों के प्रति सतर्क था और इसने अस्पष्ट और अनिर्णायक तरीके से बर्बर लोगों के साथ अपने संवाद के नियमों का उल्लेख किया जिसमें चीन की शैली को कमजोर और शाही नियति से तय बताया गया। चीन का विचार था कि राजनयिक विमर्श को व्यापार संबंधों से अलग किया जा सकता है। कोरियाई युद्ध चीन के लिए एक परिवर्तनकारी चरण था क्योंकि सोवियत , चीनी और अमेरिकी राजनयिक/सैन्य संवादों और अमेरिकी शक्ति को गति देने की चीन की क्षमता ने इसे आत्मविश्वास प्रदान किया थाऔर बात-चीत में चीन की कूटनीतिक शैली में अशिष्टता और

आक्रामकता के संकेत दिखाई दिए थे। लेकिन इससे सबक सीखे गये और चीन ने 1950 के दशक में और बांडुंग सम्मेलन में भारत-चीन संकट में एक आकर्षक कूटनीति का अनुगमन किया , जहां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अपने मूल्यांकन ने इसे एक स्वतंत्र राजनयिक रुख अपनाने के लिए प्रेरित किया। 1949 से पहले की कूटनीति कीमाओ-झोउ दृष्टिकोण और डेंग और डेंग-पश्च दृष्टिकोण से तुलना करने पर इसे धीमी , हालांकि,परिकलित, शैली और अभिविन्यास में परिवर्तन के तौर पर पाता है। हालांकि , गैर-चीनी दुनिया ने चीन के कूटनीतिक अभिविन्यास में परिवर्तन का मुख्य स्रोत प्रदान किया है। बाहरी दबावों की प्रतिक्रिया में बीजिंग परिवर्तन करता है और आंतरिक राजनीति पर इनका व्यापक प्रभाव महत्वपूर्ण है। यह समकालीन चीन की कूटनीति में एक स्थायी पैटर्न है क्योंकि यह अब अपने सामरिक हितों को आगे नहीं बढ़ा सकता है।

परिचय

चीन का गैर-चीनी विश्व के साथ संवाद, मुख्य रणनीतिक सिद्धांतों की उत्कृष्टता को उजागर करता है लेकिन वे अभी प्रवाह (चीनी भाषा में शी) की स्थिति में हैं और चूंकि उनकी अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और परिस्थितियां बदलती है इसलिए वे चीनी व्यवसायियों के द्वारा एक आंतरिक समीक्षा का सामना करते हैं। संवादों के अनुभवों ने 1800 के दशक से रूपाकार लिया और वे चीनी राजनयिक सिद्धांत में क्रमिक उत्थान, अंतर-कुलीन वाद-विवादों में विकासात्मक वृद्धि तथा समाज (घरेलू) तथा राजनयिक (बाह्य) प्रश्नों के विषय में द्विधा को दर्शाते हैं।

संक्षेप में चीन के राजनयिक विकास ने प्रगति की है और वैश्विक दृष्टिकोण के साथ इसकी कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य क्षमताओं में भी वृद्धि हुई है। एक कहावत है कि समय एक रैखिक शैली में चलता है लेकिन सरकारें उन तरीकों से कार्य करने के लिए प्रवृत्त होती हैं जो विपरीत प्रभाव पैदा करते हैं। यह अनपेक्षित परिणामों का नियम है। गलत अवधारणाओं के उपयोग से निर्णय में त्रुटियां अथवा विचारों या कार्रवाई का एक दोषपूर्ण पैटर्न जो देश के दीर्घकालिक हितों की सेवा नहीं करता है या रिश्तों (दोस्ती या दुश्मनी/प्रतिद्वंद्विता) के विकास का निर्माण करता है जो कि मौन या विक्षेपित नहीं हो सकते हैं और जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय लागतों के साथ उलझते हुए रिश्ते बनाते हैं। यहां जोखिम/इनाम अनुपात वास्तविक लाभ और अनुमानित नुकसान के आधार पर योग्यता मूल्यांकन है।

इतिहास के अध्ययन और चीन के कूटनीतिक सिद्धांत के विकास के पैटर्न को दिखाने के लिए आवश्यक है (क) समकालीन चीन की कूटनीति और वार्ता के दृष्टिकोण को 1949-पूर्व की सोच और प्रथाओं में आधार बनाया गया हैऔर (ख) जापान, रूस और पश्चिमी शक्तियों के द्वारा बनाये गये निरंतर

बाहरी दबाव नें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार,कूटनीति और विश्व व्यवस्था में चीन की स्थिति के लिए चीन के दृष्टिकोण को बदल दिया है। पहला तत्व बताता है कि चीन के पास दूसरों को स्थानांतरित करने की रणनीतिक पहल है ; दूसरा तत्व बताता है कि (क) और (ख) के बीच अब बात-चीत है और गैर-चीनी विश्वकी सूचनाएं और दबाव अब चीन के भीतर और गैर-चीनी विश्व के संबंधों में चीन के कूटनीतिक बातचीत का एक हिस्सा हैं। इसने चीन के कूटनीति दृष्टिकोण को प्रभावित किया है। 1949 से पहले और कम्युनिस्ट चीन ने दृष्टिकोण और नीतियां विकसित की हैं जिन्हें तीन प्रकार से दर्शाया जा सकता है: (क) जहां दुशप्राप्य सौदेबाजी होती है ; (ख) जहां अन्तर्निहित सौदेबाजी और पैंतरेबाज़ी होती है; और (ग) जहां अभिसरण हितों पर आधारित सौदेबाजी होती है। विशेष रूप से (ख) क्योंकि चीन के राजनयिक और सैन्य इतिहास दोस्तों और दुश्मनों के साथ संबंधों के एक निश्चित पैटर्न पर नहीं बसे हैं और जोखिम / इनाम अनुपात प्रवाह में हैं क्योंकि चीन का आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण प्रवाह में है परध्यान दिया जाना चाहिए। मेरे विचार में,अब तक (ख) ने अधिक गतिविधि (क) का उत्पादन किया है और (ग) के तहत सीमित गतिविधि है।

चीन का कारक रणनीतिक चुनौतियों के साथ विश्व इतिहास महत्व में उत्पन्न हुआ है

विकास के तीन स्वरूपों ने इस अवधि के दौरान चीन की कहानी को आकार दिया। सबसे पहलेचीन, चीनी व्यापारियों और पश्चिमी सरकारों के कार्यों में शामिल था। यह ध्यान और दबाव का एक वाणिज्यिक और कूटनीतिक उद्देश्य बन गया। दूसरा,विदेशी बर्बर लोगों से निपटने के लिए आवश्यक तरीकों के बारे में चीनी चिकित्सकों के बीच आंतरिक बहस में , कूटनीति, गठबंधन और सैन्य शक्ति की भूमिका के बारे में सवाल उठे।

तीसरा, साम्यवाद की जीत और माओवादी विचारधारा के बढ़ने के साथ, चीनी राजनैतिक विचार में कूटनीति युद्ध और मनोवैज्ञानिक युद्ध एक एकीकृत रणनीति के प्रमुख तत्व के रूप में सामने आए। युद्ध और शांति माओवादी सोच के विपरीत नहीं थे, वे युद्धाभ्यास को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक तत्व थे। इस सिद्धांत ने चीन की सोच में संतुलन की बात नहीं की , बल्कि चीन के लिए मनोवैज्ञानिक लाभ की मांग करने वाली पैंतरेबाज़ी की एक प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद , 1949 से 1970 के दशक के दौरान,चीन ने दुश्मन को सबक सिखाने के लिए नियंत्रित संघर्ष-निर्माण और वृद्धि की रणनीति अपनाई,लेकिन चीनी मूल हितों को परिभाषित करने और दुश्मन के अस्वीकार्य कार्यों का परीक्षण करने के लिए अस्वीकार्य कार्यों को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह रणनीति सिद्धांत और राजनीतिक बयानबाजी के बजाय व्यावहारिक राजनयिक-सैन्य अनुभवों से सीखने के लिए था। इसके बाद का खंड 1949-1970 के दशक की रणनीति और वार्ता की भूमिका की जांच करता है।

चीन के राजनयिक विकास विभिन्न स्तरों के माध्यम से विकसित हुए हैं

19 वीं सदी पूर्व चीन ने चीन-सार्वभौमिक केंद्र और दूसरी ओरवे बर्बर जो चीनी को सांस्कृतिक रूप से नीचा समझते थे, के बीच कूटनीति या वार्ता की आवश्यकता महसूस नहीं की थी। इन बर्बर लोगों को श्रेष्ठ चीनी संस्कृति के संपर्क में लाकर और सहायक रिश्ते बनाकर सभ्य बनाया जा सकता है। तुंग साम्राज्य (618-907 ई.),जिसने युन्नान को छोड़कर पूरे चीन को उपनिवेशित किया , ने उत्तर की भौगोलिक सीमाएँ निर्धारित कीं जिसका प्रतिनिधित्व चीन की महान दीवारकरती थीं , लेकिन दक्षिण के विस्तार के खिलाफ कोई सीमा नहीं थी। जो वर्तमान दक्षिणपूर्व और दक्षिण एशिया है)। शासकों ने गठबंधन या शक्ति कूटनीति के संतुलन पर अधिक ध्यान नहीं

दिया। चीन के मजबूत होने पर मित्रों की कोई आवश्यकता नहीं थी और यदि वह कमजोर था तो सहयोगी 'झूठे मित्र'थे।

19 वीं सदी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने चीन को जापान , रूस और पश्चिम के दबावों से अवगत कराया। इसने चीनी चिकित्सकों को इन दबावों को स्वीकार करने और उनसे निपटने के तरीके खोजने के लिए मजबूर किया। ऐसा करते हुए इसने कार्रवाई के तरीकों तथा विदेश नीति को एक अस्थायी घटना, अस्थायी गठबंधन के तौर और शक्ति के संतुलन की पश्चिमी शैली की जरूरत ना होने को उजागर किया। पारंपरिक तरीकों पर भरोसा करने के बजाय चीनी चिकित्सकों ने बर्बर लोगों के लिए चारा निर्धारित करने, अस्थायी छूट देने और इन लोगों के बीच लालच और प्रतिद्वंद्वियों पर ध्यान केंद्रित किया। चीन का दृष्टिकोण पारंपरिक प्राचीन अंग्रेजी दृष्टिकोण से अलग था। सामान्य तौर पर बात करें तो पश्चिमी रणनीति तीन तत्वों पर निर्भर हैः दण्ड का भय पैदा करने के लिए उपयुक्त शक्ति दृश्यात्मक होनी चाहिए; रणनीति में एक शिल्प की मौजूदगी (जो कि कुछ रहस्य, कुछ संदेह, लाभ के कुछ वादे), दूसरे पक्ष को प्रभावित करने के कुछ प्रलोभन ; और एक कार्रवाई अथवा अन्य बातों के साथ-साथ विपक्ष में छल-छद्म ; और अन्य लोगों के लिए ईमानदारी से दृश्यमान होना चाहिए। इन शर्तों के अधीन दुश्मन के व्यवहार को बदला जा सकता है। इस समय चीन ने न तो मजबूत बाहरी दुश्मनों से युद्ध की मांग की और न ही उनके साथ गठबंधन किया। इसने आंतरिक बर्बर लोगों को शामिल करने के लिए जो क्षेत्रीय लाभ चाहते थे (अर्थात् जापान और रूस की तुलना में अमेरिका और इंग्लैंड) बाहरी या दूर-दराज के उन लोगों की तलाश की जिनके पास चीन के खिलाफ क्षेत्रीय डिजाइन नहीं थे , वे चीन के निकट भौगोलिक निकटता में थे और जिनकी नीति ने चीन के मूल हितों और प्रतिष्ठा को प्रभावित किया। 19 वीं शताब्दी में गठित और 20 वीं शताब्दी में भी लागू हुए कई सूक्ष्म योगों ने चीन के

दृष्टिकोण को सूचित किया। सूत्रों के अनुसार,पाँच सूत्रों का सिद्धांत था,एक प्रचलित अभियान का मूल्य,यह विश्वास कि युद्धरत बर्बर चीन के लिए फायदेमंद थे क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को नकार दिया था। मनोवैज्ञानिक लाभ और प्रत्यक्ष संघर्ष के बिना और आम तौर पर स्थायी या निश्चित संरेखण के लिए एक खोज के बजाय पैंतरेबाज़ी की नीति का पीछा करके विजय की मांग की गई थी। (चीन की इच्छानुसार समर्पण करने वालों के लिए उपहार, मनोरंजन, महिलाओं और शाही स्वागत के माध्यम से दुश्मन को भ्रष्ट करना था)। इसका मूल आधार पुराना था: चीन मध्य साम्राज्य, मध्य देश और नीति का उद्देश्य दुश्मन के मनोबल को कम करना और इसे एक प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक स्थिति में रखना था। धोखा और हेराफेरी चीन के लिए स्वीकृत कूटनीतिक आदर्श था।

हालांकि,अस्थायी आवास और बर्बर प्रतिद्वंद्वियों की उत्तेजना की इस नीति ने चीन के खिलाफ विदेशी दबाव को दुनिया के प्रति और उसके दृष्टिकोण और उसके स्थान के विरुद्ध विदेशी दबावों का निपटान नहीं किया। प्रादेशिक और वाणिज्यिक कृषि का लालच 19 वीं शताब्दी में प्रमुख शक्तियों की औपनिवेशिक नीतियों के लिए केंद्रीय थालेकिन हमारे विश्लेषण के लिए इस तरह के खतरों का अस्तित्व एक महत्वपूर्ण,यद्यपि अर्त-कुलीन,चीनी व्यवसायिकों के बीच बहस को उत्तेजित करता था। इस बहस के मापदंडों को 1800 के मध्य में निर्धारित किया गया था यहां तक कि माओत्से तुंग और साथी औपनिवेशवादियों ने क्रांतिकारी हिंसा के महत्व,चीन के नेताओं की माओ-पश्च,डेंग-पश्च ज़ियाओपिंग और पोस्ट- हू जिंटो की सोच और प्रथाओं में कूटनीति, सैन्य बल और मुख्य हितों की उचित भूमिका को स्पष्ट करते हुए बहस को आगे बढ़ाया।यह संभावना नहीं है कि 2012 में नए नेताओं का चयन इस बहस को दूर करने योग्य परिस्थितियों में सुलझाएगा। चीन की आंतरिक वाद-विवाद का एक अध्ययन एक उपयोगी अभ्यास है क्योंकि एक

तरफ वे दुविधाओं और बार-बार के दबावों के अस्तित्व को प्रकट करते हैं जिनके लिए नीतिगत विकास की आवश्यकता होती है , और दूसरी ओर वेअर्थात् प्रतिरोध के बिंदु,परिवर्तन और क्षेत्रों जहां बदलाव संभव या होना प्रतीत होते है उनके के लिए बेंचमार्क निर्धारित करते हैं। यह 1949 के बाद से चीनी कूटनीति की सफलताओं और विफलताओं का मूल्यांकन करने के लिए संदर्भ या ढांचा है और उन परिस्थितियों और मुद्दों के विकास के लिए जिन्होंने चीनी पेशेवरों को वार्ता पदों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है , जिन्हें 'दुशप्राप्य', 'युद्धाभ्यास और सौदेबाजी' के रूप में या 'अभिसरण वार्ता', जो सीमित समझौते का उत्पादन करती हैउनके रूप में चिह्नित किया जा सकता है। मेरे विचार में1800 के मध्य से चीन की कूटनीतिक सोच का विकास अभी भी प्रगति पर है।

साम्यवादी चीन की 1949 के बाद की रणनीति उजागर करती है कि 1949 से कई प्रमुख बदलाव हुए हैं।1800 के मध्य की बहस माओ के विचार में गई कि शक्ति केवल बंदूक की नली से आती है। यह चीन को अपनी पारंपरिक स्थिति से अलग ले गया, क्योंकि देश के केंद्र में सांस्कृतिक श्रेष्ठता के आधार पर एक नए दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के साथ प्रतिष्ठा थी कि यह एक क्रांतिकारी दुनिया (1949-1960) का केंद्र था। 1970 के बाद से दो और बदलाव हुए। क्रांतिकारी विषय और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से औरएक आशय से कि चीन एक सामान्य देश है शक्ति को आर्थिक और सैन्य आधुनिकीकरण के माध्यम से सत्ता' के पक्ष में छोड़ दिया गया था यह संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ और विश्व समुदाय के एक सदस्य के रूप में शांतिपूर्ण वृद्धि और भागीदारी की मांग की।

1970 के बाद से सेना और राजनयिक कूटनीति को ध्यानपूर्वक जाँचने की आवश्यकता है क्योंकि एक ओर, स्पष्ट रूप से इसकी राजनीतिक

बयानबाजी और कूटनीतिक शैली में परिवर्तन हुआ और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक, सैन्य और आर्थिक मामलों में चीन की उपस्थिति एक अभूतपूर्व तरीके से बढ़ी, लेकिन दूसरी ओर यह स्पष्ट नहीं था कि क्या यह अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में उसके द्वारा बनाय गये दबाव परिणाम था या चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत और उसके मूल क्षेत्रों और अन्य हितों की रक्षा के लिए उसके दृढ़ संकल्प के कारण अवसर और प्रोत्साहन से बलपूर्वक कार्य करने के लिए, और/अथवा यदि ये परिवर्तन एशियाई और वैश्विक रणनीतिक और आर्थिक खेल में चीन को एक बड़ा खिलाड़ी बनाने के लिए कट्टरपंथी नए दृष्टिकोण को अपनाने का परिणाम थे। कोरियाई युद्ध मेंइसने अप्रत्यक्ष संघर्ष के लिए अपनी पुराने हितैषियोंको सुरक्षित किया और एक बर्बर शक्ति को लड़ने और दूसरे को बेअसर करने के लिए आगे कर दिया। (कोरियाई संघर्ष में स्टालिन ने संयुक्त राज्य अमेरिका से लड़ने से इनकार कर दिया और चीन को यह काम करने दिया)।कोरियाई युद्ध और चीन-भारतीय संघर्ष में अपनी भागीदारी के द्वारा, यदि आवश्यक हुआ तो ताइवान को बलपूर्वक मुक्त करने की उनकी धमकी से , और 1950 के दशक में क्वेमोय और मात्सू की गोलाबारी से, चीन ने विदेशी संबंधों में चुनिंदा परिस्थितियों में युद्ध के खतरों की उपयोगिता का अनुमान लगाया। इन कार्रवाइयों ने वारसॉ में अमेरिका-चीन राजनयिक संपर्क और बाद में अमेरिका-चीन-रूस रणनीतिक त्रिपक्ष के गठन के लिए आधार तैयार कियाजो 1971-72 में चीन और अमेरिका के बीच हुए समझौतों की सफलता पर पहुंच गया। ये घटनाएँ दो महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती हैं? भले ही एशियाई रणनीतिक मामलों में चीन कारक महत्वपूर्ण हो गया है,लेकिन क्या चीन अभी भी केंद्रीय देश है ? जैसा कि पारंपरिक रूप से माना जाता है। 1950 और 1960 के दशक की घटनाएँ और 1979 में वियतनाम के साथ संक्षिप्त संघर्ष के मामले में दो अलग-अलग उत्तर प्रदान करते हैं। पहला यह है कि चीन अपने दक्षिणी क्षेत्र में मध्य देश बना हुआ है

जो अफगानिस्तान से दक्षिण चीन सागर तक हिंद महासागर सहित फैला हुआ है। उनके दक्षिणी क्षेत्र में चीन की दो नस्लें हैं। सबसे पहले , भू-राजनीति और शाही इतिहास दक्षिणी क्षेत्र और रूसी , तिब्बती और ब्रिटिश भारत की नीतियों के दबाव की ओर ध्यान आकर्षित करतें हैं। 1949 के पूर्व के दृष्टिकोणों का तिब्बत और शिनजियांग क्षेत्रों में चीन की सैन्य और राजनीतिक उपस्थिति और हिमालयी क्षेत्र में उसके सैन्य ढांचे के निर्माण में परिवर्तन हुआ है। दूसरा कारण यह है कि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिणी क्षेत्र को स्थिर करने के लिए एक दूसरे के साथ साझेदारी को महत्वपूर्ण मानते हैं और इस संबंध में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अस्थिर स्थिति से पहले भी , निक्सन, क्लिंटन और ओबामा राष्ट्रपति ने भारतीय उपमहाद्वीप में चीन के हितों और अधिकारों को मान्यता दी है। 1949 से पहले के चीनी शासकों ने उत्तरी विस्तार की सीमा तय की थीलेकिन दक्षिणी विस्तार के लिए कुछ तय नही किया गया था और दक्षिण 1949 से लगातार चीन के रणनीतिक (सैन्य और आर्थिक) विस्तार की रणनीतिक दिशा रहा है जोतिब्बत के अधिग्रहण से प्रारंभ होकर,शिनजियांग में उसकी स्थिति का मजबूत होना, झिंजियांग में सोवियत संघ के कानूनी अधिकारों और वाणिज्यिक उपस्थिति को हटाना व इसके बाद हिमालय क्षेत्र और दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की उपस्थिति का विस्तार तक है। यहां चीन की गतिशीलता और मनोवैज्ञानिक लाभ नाटकीय रूप से बढ़ गए हैं। ये लाभ पारंपरिक , 1949 से पूर्व और 1949 के बाद के माओवादी उद्देश्यों के अनुरूप हैं। दूसरा उत्तर , हालांकि, सुदूर पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में चीन की स्थिति से संबंधित है। माओवादी चीन ने कोरियाई युद्ध में बेहतर अमेरिकी सेनाओं के रास्ते मे गतिरोध पैदा किया,मंचूरिया और झिंजियांग में सोवियत क्षेत्रीय लाभ वापस ले लिया,1960 के दशक तक सोवियत वैचारिक और कूटनीतिक नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया,अपमानित भारत जो किसोवियत संघ और संयुक्त राज्य

अमेरिका दोनों का मित्र था ने,जापानी सैन्यवाद और जापान और दक्षिण कोरिया के अमेरिकी पुनर्गठन के खिलाफ एक अभियान पर आगे बढ़ा। लेकिन जापान, ताइवान और दक्षिण कोरिया ने सैन्यविरोध नहीं किया , संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके एशियाई सहयोगियों के बीच सैन्य संबंध मजबूत और विश्वसनीय हुए,और सैन्य आधुनिकीकरण और औपचारिक या अर्ध-औपचारिक गठजोड़ या संरेखण के साथ एक क्षेत्र में,चीन एक महत्वपूर्ण देश है लेकिन प्रशांत,दक्षिण पूर्व एशियाई और हिंद महासागर मामलों में यह केंद्रीय देश नहीं। अब इसे बार-बार यूएन के सदस्य के रूप में एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय हितधारक के रूप में काम करने के अपने दायित्व के बारे में याद दिलाया जाता है, क्या माओ को यह तर्क देने का अधिकार था कि यू.एन. सदस्यता से चीन की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता में कमी आएगी ?25 अप्रैल, 1961 को चीनी सेना को गुप्त निर्देशों में,बीजिंग ने तर्क दिया कि :यदि हमारा देश संयुक्त राष्ट्र में शामिल होता है,तो हमारे पास मतदान में बहुमत नहीं हो सकता है ; औपचारिक रूप से कठिन स्थिति को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है,लेकिन वास्तव में जो संघर्ष होता है वह अधिक हिंसक होगा और हम अपनी वर्तमान स्वतंत्रता को खो देंगे। 1949 से पहले चीन पश्चिमी व्यापारियों और सरकारों को दबाव और घेराव से बचने के लिए अस्थायी रियायतें देने पर विश्वास करता था और इसने प्रवेशद्वार पर बर्बर लोगों की जाँच करने के लिए दूर के बर्बर की भूमिका निभाई। यह गठबंधनों और बिजली नीति के संतुलन से बचा रहा। 2012 में,यह एशिया के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में संरेखण और गैरचीनी गठबंधनों के साथ आमने-सामने है और ये एक बढ़ते चीन के बढ़ते संदेह परआधारित हैं। परिणामतः यह अपने आप को किसिंजर / निक्सन यात्राओं के साथ शुरू एक शक्ति कूटनीति के संतुलन में शामिल देखता है और 2012 तक इसने विस्तृत होकर जापान , ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों (विशेष रूप से फिलीपींस और भारत) को भी शामिल

कर लिया है। भले ही ये देश चीन के खिलाफ संयुक्त घेराव अभियान को बढ़ाने या सार्वजनिक रूप से घोषित करने का इरादा नहीं रखते हैं कि यह एक दुश्मन राज्य है फिर भी चीन के चारों ओर संरेखण के निर्माण में इन देशों की भागीदारी चीन के पारंपरिक सोच की प्रक्रिया में अलगाव और घेरने की आशंका पैदा करती है।

जबकि, चीन की अभूतपूर्व आर्थिक और सैन्य वृद्धि ने विश्व राजनीति में उसके पदचिह्न को बढ़ा दिया है,संरेखण का उदय जो चीन को संलग्न करने के लिए है,दक्षिण चीन के समुद्र में उसके साहसी आवेगों की जांच करने के लिए भी काम कर सकता है।

संक्षेप में,साम्यवादी चीनी कूटनीति ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को बदलने के लिए खुद को समायोजित किया है। यह अपने दक्षिणी क्षेत्र (हिमालयी क्षेत्र और दक्षिण एशिया) के मामलों में मुख्य देश के रूप में कार्य करता है और यह उसके पारंपरिक दृष्टिकोण से मेल खाता है जोदक्षिण की ओर विस्तार की सीमा को मौजूद नहीं रखता है। यहां राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य मामलों में उसके पदचिह्न को बढ़ाने के अवसर एशिया के तीन प्रमुख क्षेत्रों के कारण हैं। 1945 में,यूएसएसआर एक क्षेत्र के नियंत्रण में था और चीन ने दूसरे क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त किया। भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया से यूरोपीय साम्राज्यों का पीछे हटना दक्षिणी क्षेत्र को एक शक्ति शून्य में छोड़ दिया , जिसे भारत 1947 में नियंत्रित नहीं कर सका था। लेकिन दूसरा समायोजन सुदूर पूर्वी क्षेत्र में है जहां चीन के मुख्य देश के रूप में कार्य करने की क्षमता को उसके पड़ोसियों और अमेरिका की नीतियों द्वारा बाधित कर दिया है। 1961 के प्रारंभ में,चीन के चिकित्सकों ने दुनिया में बिजली के प्रसार के निहितार्थ को मान्यता दी,क्योंकि चीन का महत्व बढ़ गया था। पूर्व में उल्लिखित गोपनीय निर्देशों में कहा गया था: 'चीन की भागीदारी के बिना दुनिया की कोई भी महत्वपूर्ण

समस्या हल नहीं हो सकती।हालांकि , अन्य विचारों से, हमने यह भी देखा है कि चीन की भागीदारी के साथ , दुनिया की समस्याओं को पूरी तरह से समाधान के लिए केवल कुछ शक्तियों पर निर्भर नहीं किया जा सकता है... '। यह एशिया प्रशांत और हिंद महासागर के दृश्य का एक बड़ा चरित्र है , जिसमें बड़ी और मध्यम शक्तियों के प्रसार के साथ प्रतिस्पर्धात्मक हितों और बढ़ती आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक क्षमता और कौशल के प्रसार की क्षमता है। नई स्थिति 1961 में दुनिया के प्रति बीजिंग के दृष्टिकोण से एकदम अलग है। पश्चिमी और जापानी दबावों और 1800 के दशक में हस्तक्षेप के अपने अनुभवों से चीन की दुनिया के दो प्रमुख प्रतिपादकों माओ त्से-तुंग और चाउ एनलाईने वैश्विक विचारों के आधार पर चीन को विदेशी साम्राज्यवाद का शिकार और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ एक सेनानी के रूप में बताया। यह 1800 के बाद से और 1960 के दशक के अंत तक चीन के कूटनीतिक संवाद का एक क्रमिक विषय था। 'बुलेटिन ऑफ एक्टिविटीज ' (1961) में 'चीनी सेना को गुप्त निर्देश ,25 अप्रैल,1961' को इस प्रकार दर्ज किया गया है: 'हमें समाजवादी खेमे को एकजुट करना होगा ,उपनिवेशों और अर्ध उपनिवेशों के लोगों के संघर्ष का सक्रिय रूप से समर्थन करना होगा, सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास करें ,भारत में नेहरू और यूगोस्लाविया में टीटो सहित क्षेत्र को अलग करें और अमेरिकी साम्राज्यवाद का विरोध करें'।

चर्चा से संकेत मिलता है कि चीन की गैर-चीनी दुनिया के साथ 1949 के बाद के राजनयिक और सैन्य अनुभवों ने उसके विचार और कार्रवाई के 1949 के पहले के ढ़ाचे को कम कर दिया है। इनमें से कुछ अटूट हैं और कुछ को संशोधन की आवश्यकता हैं। मैं पारंपरिक चीनी विचारों में समाहित रणनीतिक विचारों को संक्षेप में नीचे प्रस्तुत करता हूं जो अभी भी अव्यवहार्य तथा संशोधन योग्य विचारों की तुलना में प्रचालन योग्य हैं।

चीन के विदेश संबंधों में गतिशीलता का स्थायी महत्व

पैंतरेबाज़ी करने के लिए कुछ जगरह की तलाश करना चीनी राजनयिक और सैन्य सिद्धांत और व्यवहार में निरंतर रही है। 1950 में,चीन ने स्टालिन के साथ एक मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए,एक ऐसी घटना जिसे व्यापक रूप से रूस के खिलाफ और पश्चिम के खिलाफ एक पैंतरेबाजी के रूप में माना गया था लेकिन इस पैंतरेबाजी को एक राजनयिक के रूप में देखा जाना चाहिए,न कि एक वैचारिक के रूप में। इससे पहले,चीन के साम्यवादियों की जीत से पहले,माओ ने मैत्रीपूर्ण संबंधों की तलाश के लिए वाशिंगटन में एक बदलाव किया। उन्होंने 1944-46 में और फिर 1949 में अमेरिकी समर्थन के लिए दो अनुरोध किए। दोनों को नकार दिया गया और फिर माओ ने समर्थन के लिए स्टालिन का रुख किया। इसलिए,पहलीपैंतरेबाजी वाशिंगटन की ओर और दूसरी मास्को की ओर थी। लेकिन मास्को पैंतरेबाजी अस्थायी थी और चीन-सोवियत विभाजन ने विचारधारा,सैन्य और राजनयिक मुद्दों के संदर्भ में विवाद का खुलासा किया। मास्को के साथ विभाजन से पहले,चीन ने कोरियाई युद्ध में त्रिकोणीय कूटनीति से निपटना सीखा। इसने नाममात्र सोवियत समर्थन और हेरफेर के साथ अमेरिका की बेहतर सैन्य शक्ति का सामना किया। इसके बाद,इसने दोनों महाशक्तियों का सामना करने और समाजवादी खेमे के सच्चे नेता के रूप में एक दावे को आगे बढ़ाने के लिए एक रुख विकसित किया। 1960 और 1970 के दशक की अवधि के लिए इसने तीसरी दुनिया के एक प्रमुख खिलाड़ी और दोनों महाशक्तियों के साम्राज्यवाद के विरोधी के रूप में खुद को विकसित करने की कोशिश की। विचारधारा को भूलकर सामरिक हितों और सामरिक विचारों की प्रधानता पर बल देते हुए,इसने पाकिस्तान के साथ राजनयिक और सैन्य संबंध बनाए और भारत के साथ सैन्य और मनोवैज्ञानिक लाभ हासिल करने के लिए एक संक्षिप्त युद्ध किया। इस मामले में,इसने तीसरी दुनिया में शांतिपूर्ण सह-

अस्तित्व के लिए अपने मामले का निर्माण करने के लिए भारत के पहले उपयोग के खिलाफ पैंतरेबाज़ी की। इसने नेपाल,पाकिस्तान और बर्मा के साथ सीमा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए (मैकमोहन रेखा की वैधता को स्वीकार करते हुए इसे भारत के साथ बातचीत के आधार के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया)। इन पैंतरेबाजियों के द्वारा, इसने स्वंय को दो बड़ी शक्तियों के विरूद्ध खड़ा कर दिया, यूरोपीय साम्यवादी पक्षों के साथ-साथ समाजवादी खेमे के सच्चे नेता का दांव प्रस्तुत किया, तीसरे विश्व में स्वंय को शांतिप्रिय देश के तौर पर स्थापित किया तथा स्वंय को एक पारंपरिक और परमाणु आयुध दोनों के विकास द्वारा स्वतंत्रता की नीति के अनुयायी के रूप में तैनात किया।1970 के दशक की शुरुआत में प्रमुख मजदूरों का एक और समूह तैयार हुआ। चीन ने अपने क्रांतिकारी सिद्धांत और सशस्त्र संघर्षपूर्ण बयानबाजी को छोड़ दिया। इसने अमेरिका के साथ एक रणनीतिक संबंध बनाया क्योंकि दोनों के बीच सोवियत संघ के खिलाफ अभिसरण हित था और दोनों को एक-दूसरे की आवश्यकता थी क्योंकि वे अपने हितों का पालन नहीं कर सकते थे। इसने यूएस-जापान सैन्य लिंक के मूल्य को भी स्वीकार किया और निक्सन की इस बात को मान्यता दी कि जापान के साथ अमेरिकी संधि ने जापानी सैन्यवाद की जाँच की और इस संबंध के बिना एक तटस्थ जापान सोवियत प्रभाव के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रीय खतरे के रूप में जापानी सैन्यवाद के खिलाफ वर्षों तक अनुभव करने के बाद निक्सन के दृष्टिकोण के प्रति बदलाव ने नेतृत्व की सोच में एक बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा,ताइवान के उभरने में देरी को स्वीकार करते हुए,यह इस क्षेत्र में अमेरिका की स्थायी उपस्थिति के मूल्य को आँख बंद करके स्वीकार करता है। इधर,चीन सुदूर पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति परंपरा के शास्त्रीय यूरोपीय संतुलन में एक प्रशिक्षु की तरह काम कर रहा था , लेकिन यह विडंबना है कि पश्चिमी शक्तियों ने चीन के साम्यवादी नेताओं को

आधुनिक कूटनीतिक सोच कि वह विदेशियों पर प्रतिबंध लगा सकता है के अनुकूल बनाने में सफलता हासिल की थी,जो चीन के प्रति विरोध था।

चीन के कूटनीतिक विचार,जो चीन की कूटनीतिक और सैन्य यात्रा बन गए,हालांकि,यह दर्शाते हैं कि कुछ विचारों में संशोधन की आवश्यकता है। चीन का मध्य साम्राज्य सिद्धांत अभी भी प्रासंगिक है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह वर्तमान चीनी विचार प्रक्रिया में एक मुख्य तत्व है और इसमें चीन की कार्रवाई को निर्धारित करने की सीमा भी अस्पष्ट है। चीन के लिए चीनी शब्द आज भी चुंग कुओ या 'मध्य साम्राज्य के लिए' है; 'चाइना', आधिकारिक और शैक्षणिक संवाद में प्रयुक्त शब्द,एक गैर-चीनी निर्मित है। बर्बर लोगों से निपटने का एक आधिकारिक इतिहास है। चीन का विदेश मंत्रालय 1861 में स्थापित किया गया था जिसने 'बर्बर मामलों के कार्यालय' जिसे 'सभी राष्ट्रों के मामलों के सामान्य प्रबंधन के लिए कार्यालय ' के रूप में भी जाना जाता था को स्थानांतरित किया था। आधिकारिक और अकादमिक व्यवसायी के लिए एक प्रश्न यह है कि क्या चीनी विदेश मंत्रालय की स्थापना और चीनी में मध्य साम्राज्य के नाम का प्रतिधारण-चीनी आबादी के लिए है- जिसका कि अर्थ पारंपरिक रवैये में बदलाव के बिना केवल एक कॉस्मेटिक संस्थागत परिवर्तन है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक प्रणाली के सदस्य के रूप में,चीन राष्ट्रों के बीच संप्रभुता और कानूनी समानता के आदर्श का पालन करता है लेकिन मध्य साम्राज्य के चरित्रांकन से सांस्कृतिक और नस्लीय श्रेष्ठता के प्रति प्रतिबद्धता का पता चलता है।प्रतिस्पर्धात्मक प्रमुख और बड़ी व छोटी शक्तियों से प्रभावी विश्व में,मध्य साम्राज्य के परिसर में राष्ट्रवाद का वर्चस्व रखने वाली देश में एक प्रभावी सिद्धांत के रूप में कार्य करने की संभावना नहीं है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों के अनुभवी चिकित्सकों को मध्य साम्राज्य के सिद्धांत से प्रभावित होने की संभावना नहीं है , हालांकि कुछ कमजोर राज्यों को चीन के प्रतिबंधों को स्वीकार करने के लिए लुभाया जा

सकता है। 1949 से पहले,चीन के पास विदेशी अधिकारियों को भ्रष्ट करने के लिए 'पाँचप्रलोभन' के उपयोग सिद्धांत था। किसिंजर इनको मानता है। लेकिन इन प्रलोभनों का अत्यधिक उपयोग आधुनिक संचार की आधुनिक दुनिया और सोशल मीडिया में भी हो सकता है। अफ्रीकी देशों ने चीनी कंपनियों और उनके राज्य प्रायोजकों की व्यावसायिक प्रथाओं की आलोचना करना शुरू कर दिया है और 'चीनी उपनिवेशवाद'के बारे में खुलकर बात की है। म्यांमार के साथ चीन के संबंध, इस संबंध का खुलासा कर रहे हैं। 1980 के दशक के प्रारंभ के बाद से,म्यांमार को चीन के एक ग्राहक राज्य के रूप में माना जाता था,क्योंकि सैन्य सरकार के अलगाव के कारण,म्यांमार की नजदीकी युन्नान और चीन को म्यांमार के माध्यम से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक और सैन्य संपर्क बनाने की आवश्यकता थी। लेकिन म्यांमार ने दिखाया है कि यह एक ग्राहक राज्य नहीं है,उसकी राष्ट्रवाद और राजनीतिक चेतना म्यांमार की राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन की एक मजबूत विशेषता है,और चीन की सहायता से बनाई जा रही एक प्रमुख सिंचाई परियोजना को निलंबित करने की उसकी हालिया कार्रवाई से क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को धक्का देने की इच्छा जाहिर होती है। पारंपरिक विचारों का एक और समूह आधुनिक परिस्थितियों में अयोग्य दिखाई देता है , जिसमें माना जाता है कि चीन के पड़ोसी अपने सैन्य और राजनयिक मोर्चों की सुरक्षा में लगे हुए हैं और वे चीन की कार्रवाई और वार्ता कार्यसूची के बीच के अंतर को समझते हैं। ये विचार कि बर्बरों के बीच युद्ध चीन के लिए शुभ होते हैं , कि चीन के खिलाफ दुश्मन के गठबंधन का गठन रोका जा सकता है और इसे रोका जाना चाहिए और चीन को विचलित संघर्ष की स्थितियों को विकसित करने और दुश्मन के समक्ष घुटने टेकते हुए मनोवैज्ञानिक लाभ प्राप्त करने, पर चीन के अधिकारियोंऔर शैक्षणिक चिकित्सकों को फिर से सोचने की आवश्यकता है।

फिर भी,रणनीति और कूटनीति के लिए चीन के दृष्टिकोण में सूक्ष्म परिवर्तन नोट किए जा सकते हैं लेकिन अनिवार्य परिवर्तन के बिंदुओं की निरंतरता के बिंदुओं के साथ तुलना की जानी चाहिए। यह परिवर्तन चीन के शांतिपूर्ण उदय पर बयानबाजी के तनाव का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन एक अनुभवी पर्यवेक्षक निरंतरता पर भी ध्यान देगा। नए रुख ने मूल हितों के अस्तित्व को इंगित करने और चीन की लाल रेखाओं के अस्तित्व को इंगित करने के लिए बल के उपयोग के माओ के सिद्धांत को प्रतिस्थापित नहीं करता हैऔर दुश्मन की लाल रेखाओं की खोज के लिए संकटों का उपयोग करने के लिए। माओ ने इसे 'अनुभव द्वारा सीखना' का नाम दिया। सैन्य संकट में भाग लेना युद्ध तक ले जा सकता है जैसा कि कोरिया, भारत और वीयतनाम के युद्धों में हुआ लेकिन यह संकट प्रबंधन और शत्रु के इरादों के परीक्षण तक भी ले जा सकता है जैसा कि 1950 से क्यूमोय, माओत्से और ताइवान के संबंध में शैलिंग और सैन्य संगठित करने के मामले में था। युद्ध में सैन्य गतिरोध होने पर चीनी चिकित्सक के लिए कूटनीति एक महत्वपूर्ण उपकरण बन जाती है। कूटनीति कुछ एजेंडा आइटमों को व्यवस्थित करने और तनाव को कम करने में मदद कर सकती है,जबकि रणनीति चीन के चयन के समय सामान्य टकराव और नियंत्रित वृद्धि की क्षमता को बनाए रखने में मदद करती है। चीन के हाथों में तनाव को बढ़ाने या कम करने के लिए पहल को जारी रखना और दुश्मन को व्यस्त रखने का मनोवैज्ञानिक लाभ प्राप्ति का मानक हैं लेकिन कूटनीति एक उपयोगी उपकरण नहीं है अथवा यदि लड़ाई जीत और शत्रु के आत्मसमर्पण तक जाती है तो इसका मूल्य सीमित है। जिसका परिणाम एक विजेता की शांति होगी।

चीन की शासनकला में कूटनीति की भूमिका तथा नियंत्रित वृद्धि और युद्ध की तैयारी की भविष्य की संभावना: 21वीं सदी में चीन

19 वीं शताब्दी में,चीनी कूटनीति, घेरने से बचने के लिए अस्थायी रियायतें देने,मनोवैज्ञानिक लाभ प्राप्त करने,खोए हुए क्षेत्रों को पुनर्प्राप्त करने और एशियाई मामलों में चीन को लाने के सिद्धांत का एक हिस्सा थी। जैसे-जैसे चीन विदेशी दबाव में आता गयाउसे गैर-चीनी दुनिया से निपटने में कूटनीति और सैन्य शक्ति की भूमिका की सराहना मिली। 20वीं शताब्दी में स्व-सहायता के माध्यम से इसने 1949 में तिब्बत और शिनजियांग में अपनी स्थिति से उबरने और मंचूरिया में स्टालिन को पीछे धकेलने की अपनी क्षमता के साथ जिससे उनकी श्रेष्ठ अमेरिकी शक्ति को गति मिली। कोरिया , 1962 में भारत की हार से , और तीसरी दुनिया और दक्षिण पूर्व एशियाई मामलों के विचार-विमर्श में प्रवेश करने की अपनी क्षमता से विश्व स्तर पर एक स्थान प्राप्त किया।इसने यू.एन. प्रणाली के बाहर इसे प्राप्त किया क्योंकि इसमें यू.एन. या वियना कन्वेंशन के राजनयिक मानदंडों के अनुसार कार्य करने की जिम्मेदारी के बिना उसके हित में कार्यकरने की गतिशीलता थी।

ध्यान दें कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में चीन की स्थिति और कूटनीतिक प्रथाओं की तुलना में परिवर्तन की दर या गति और इसका दायरा बहुत बड़ा था। शी एक विकासशील स्थिति की 'संभावित ऊर्जा' को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला चीनी शब्द है। 19वीं शताब्दी में ऊर्जा पश्चिमी चीन के व्यापारियों से आई और दिशा शाही चीन को पश्चिमी वाणिज्यिक और राजनयिक संवाद के लिए खोलने और अस्थायी रियायतों के माध्यम से बर्बर लोगों का प्रबंधन करने की अपनी क्षमता में शाही व्यवस्था के विश्वास को कम करने के लिए थी। 20 वीं शताब्दी के पहले भाग में ऊर्जा माओवादी गुरिल्लाओं और माओवादी विश्वासों और मार्गदर्शन से आई, जिसने

चीन को एकल पार्टी और केंद्रीय नियंत्रण में ला दिया। यह विकास चीन को एक नए और उच्च प्रेरित राज्य का केंद्र बनाना था। जो प्रमुख आंतरिक सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध था,और क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए समाजवादी केंद्र के रूप में उभरने के लिए प्रतिबद्ध था। इस प्रकार,चीन का शी तब ठीक था जब दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में यूरोपीय साम्राज्य विघटित हो रहे थे,भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया के दक्षिणी क्षेत्र में एक शक्ति निर्वात उभर रहा थाऔर जापान की हार के बाद,अमेरिकी सरकार सुदूर पूर्व में अपने गठबंधन का आयोजन कर रही थी लेकिन स्थिति अभी भी विकसित हो रही थी। अमेरिकी विदेश मंत्री डीन एचेसन ने घोषणा की थी कि कोरिया और ताइवान अमेरिकी रक्षा परिधि का हिस्सा नहीं थे ; जापान की आंतरिक राजनीति और बाहरी नीति में सुधार वाशिंगटन के लिए प्राथमिकता थी। स्पष्टरूप सेसुदूर पूर्व में स्थिति विकसित हो रही थी लेकिन तभी कोरियाई युद्ध छिड़ गया था। स्टालिन की कोरिया नीति में अस्पष्टता के कारण,युद्ध शुरू करने के लिए उत्तर कोरियाई लोगों के लिए उनके मार्गदर्शन, चीन को सेना को सिवाय प्रतीक के रूप में सहायता की सांत्वना देकर मदद करने से इनकार कर दिया और और इस प्रकार चीन ने इसे भांपा और शक्ति के दम पर दोनों कोरियाओं को एकजुट करने के लिए अमेरिकी सेनाओं को यलू नदी के किनारे लाया जा सके। कोरियाई लड़ाई में चीनी सेनाओं के प्रवेश और अमेरिकी सेना के पीछे हटने के साथ,सैन्य लाइनों को स्थिर किया गया और सैन्य-बलों के विन्यास के मापदंडों को स्थापित किया गया। *शी* की संभावित ऊर्जा एक सैन्य और राजनीतिक गतिरोध और एक विभाजित कोरिया में निहित है जो चीन के रणनीतिक हितों के अनुकूल (और अभी भी सूट करता है)। अमेरिकी और चीनी वार्ताकार कड़वाहट में लगे हुए थे,लेकिन दृष्टिहीनता में, 'अभिसारी सौदेबाजी'क्योंकि दोनों पक्ष एक नया युद्ध नहीं चाहते थे ,दोनों में एक साझा समझौते के जरिए मोर्चे को स्थिर

करने का साझा हित था जो 1953 से चला आ रहा है।

शी ने बीजिंग के लिए 1950 के दशक में और 1955 में बांडुंग सम्मेलन में भारत-चीन की बातचीत के बारे में भी बताया। बढ़ती गतिशीलता की खोज ने चाउ एनलाई को बांडुंग सम्मेलन में अपनी 'आकर्षक कूटनीति' का उपयोग करने और चीन को तीसरी दुनिया की राजनीति में लाने और गुंडागर्दी में,गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों नेहरू , टिटो और सुकर्णो के प्रभाव को कम करने के लिए प्रेरित किया। स्मरण करो कि अप्रैल 1961 (पहले उद्धृत) में चीनी सेना को जारी गुप्त निर्देशों में नेहरू और टीटो को अलग-थलग करने के लिए लक्ष्य के रूप में नामित किया गया था। चीन की कूटनीति ने इस कार्रवाई के लिए आधारशिला रखी।इसके बाद, चीन के राजनयिकों और सैन्य-कार्रवाइयों-भारत-चीन सम्मेलन में तथा वियतनाम युद्ध में वियतनाम को सैन्य सहायता प्रदान करता जिसने कि उसके मन में सोवियत कार्रवाई के लिए अविश्वास-एक स्वतंत्र और साथ-ही-साथ क्षेत्रीय शत्रुओं, वियतनाम के साथ एक सहायक की भूमिका निभाने तथा शक्ति की राजनीति के क्षेत्र को बढ़ा करने और इस प्रकार सेनाओं का वर्गीकरण करने कि जो कि एक विकासशील जगह में नई शक्ति लगे के विषय में सूचित किया। नई दिशा भारत-चीन मामलों में अमेरिका-सोवियत-चीन त्रिकोण का निर्माण करना था और ऐसा करना वियतनाम (अमेरिका के प्रतिद्वंद्वी) को सैन्य सहायता प्रदान करते हुए करना और यूएसएसआर के साथ मतभेद दिखाकर अमेरिका को कूटनीतिक समर्थन दिखाना था।

1950 के कोरियाई और भारत-चीन मामलों में चीन स्थिति को त्रिकोणीय बनाकर,एक द्विध्रुवीय खेल के रूप में छोड़ने के बजाय तीसरे खिलाड़ी के रूप में सम्मिलित करके शक्तियों के विन्यास को बदल सकता था। दोनों ही मामलों में , चीन रणनीतिक खेल में शामिल होने में सफल रहा

था और इसकी कूटनीति और बातचीत के तरीके अभिसमय सौदेबाजी में भाग लेने के लिए थे जबकि वहाँ पर खिलाड़ियों जैसे कि चीन और अमेरिका के हितों में बातचीत का एक क्षेत्र मौजूद था।

लेकिन दो अन्य उदाहरणों में,1962 में भारत के साथ युद्ध और वियतनाम के साथ 1979 के युद्ध में,चीन ने दोनों को सबक सिखाने और वार्ता की स्थिति में दस्तक देने का प्रयास किया।जिससे चीन को एक मनोवैज्ञानिक लाभ मिला, जिसने एक मिश्रित रिकॉर्ड बनाया। सैन्य कार्रवाइयों ने अनपेक्षित परिणामों को प्रदान किया,स्थिति उस प्रकार विकसित नहीं जैसा बीजिंग चाहता था और लंबे समय में बलों के बदलते विन्यासों ने क्षेत्र में शांति हासिल करने के लिए कई सीमा समझौतों के रूप में सीमित अभिसरण वार्ताओं का मिश्रण बनायाऔर भारत और वियतनाम के साथ राजनयिक,व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों की स्थापना,लेकिन इसने चीन के साथ एक रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता का भी प्रारंभ कर दिया। हम चीन-भारत सीमा वार्ता पर आक्रामक तेवर, पोषित कार्यसूची देख रहे हैं। विवादित सीमा की लंबाई के बारे में दोनों पक्षों के अलग-अलग विचार हैं। अक्साई चिन चीन के लिए एक सुलझा हुआ मामला है,भारतीय कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है,पाकिस्तान कश्मीर और चीन कश्मीर नहीं है,और अरुणाचल प्रदेश 'दक्षिणी तिब्बत'है। भारत इन स्थितियों को स्वीकार नहीं करता है। ये प्रतिस्पर्धी एजेंडा विकासशील स्थिति का एक हिस्सा हैं और ये एक स्थापित प्रवृत्ति नहीं बनाते हैं। वियतनाम के साथदक्षिण चीन सागरों में संसाधन अधिकारों पर क्षेत्रीय असहमति दुशप्राप्य सौदेबाजी के लिए है। अकादमिक और सरकारी अभ्यास के लिए चुनौती उन परिस्थितियों को परिभाषित करना है जो स्वयं को अभिसिंचित सौदेबाजी या मौन सौदेबाजी या पैंतरेबाजी या दुशप्राप्य सौदेबाजी के लिए उधार देती हैं।

चीन की समझौतों की रणनीतियां और अभिप्रेत उत्तराधिकारी और अनभिप्रेत स्थितियां

वार्ता के लिए चीन का दृष्टिकोण जटिल है क्योंकि इसे विभिन्न रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

(क) यह दुर्ग्राह्य सौदेबाजी का एक रूप है जो अपारदर्शी है और युद्ध या समझौता वार्ता का कारण बन सकता है परंतु अक्सर दूसरे पक्ष को मुश्किल में डाल देता है, दूसरे पक्ष को व्यस्त रखने के लिए तनाव और अनिश्चितता के स्तर को बनाए रखता है और 'वार्ता क्षेत्र' तथा 'कार्यवाही क्षेत्र' दोनों को तैयार करता है। हालांकि , वार्ता में कार्यवाही का अनुपात , अस्पष्ट है और यह संबंधों में एक परिवर्तनशील तत्व है।

माओ ने हेनरी किसिंजर को बताया कि भारत को वापस वार्ता के लिए तैयार करने के लिए चीन को बल प्रयोग करना पड़ा।वर्ष 1949 से पूर्व चीन ने सीमा पर दुर्ग्राह्य सौदेबाजी का प्रयोग किया।उसके वार्ताकार ने मैकमोहन रेखा पर आद्याक्षर किए लेकिन 1914 के समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया। राजनयिक व्यवहार में , किसिंजर नोटों के अनुसार, आद्याक्षर सेपाठ अवरूद्ध हुआ; हस्ताक्षर करने से यह लागू हुआ। चाउ एनलाई ने अक्साई चीन के लिए मैकमोहन लाइन का व्यापार करने का प्रस्ताव दिया था लेकिन नेहरू ने व्यापार को नजरअंदाज कर दिया।12 इसका अभिप्राय नेहरू की सीमा क्षेत्रों में फॉरवर्ड पॉलिसी की गति को रोकने और उसे दुनिया में अलग-थलग करने का था। माओ का दृष्टिकोण बताता है कि 1914 का समझौता जिसने हिमालयी मानचित्र पर मैकमोहन रेखा की स्थापना की और भारत के सीमा दावे के आधार पर काम करता है , चीन के कम्युनिस्टों के लिए दुर्ग्राह्य सौदेबाजी का एक रूप था। लेकिन भारत-चीन वार्ता (या बातचीत) के अनुभव , दुर्ग्राह्य

से संभावित केंद्राभिमुख रूप से दुर्ग्राह्य सौदेबाजी के लिए बदलने और फिर से संभावित केन्द्राभिमुख सौदेबाजी की ओर बदलाव का एक स्वरूप दिखाते हैं। यह मूल्यांकन निम्नलिखित टिप्पणियों पर आधारित है। राजनयिक प्रोटोकॉल में 1914 में जब ब्रिटिश , चीनी और तिब्बती वार्ताकारों ने मैकमोहन लाइन समझौते पर हस्ताक्षर किया , जिसने चीन और अन्यों के मध्य समझौते को विफल कर दिया , चीन द्वारा इसे अंगीकार करने का अर्थ था कि समझौते को अमल में नहीं लाया जा सकता है।बाद में, चाउ एनलाई ने नेहरू को पूर्व में मैकमोहन रेखा हेतु चीन की स्वीकृति के बदले में अक्साई चीन पर चीन के दावे को स्वीकार करने के बीच एक लेन देन का प्रस्ताव दिया। यह संभावित केन्द्राभिख सौदेबाजी करने का एक प्रयास था।परंतु नेहरू ने चाउ के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और वार्ता की प्रक्रिया 1962 युद्ध में परिवर्तित हो गई, और 1980 के दशक के बाद दोनों पक्षों ने राजनयिक संबंध और सीमा वार्ता को फिर से शुरू करने के बारे में बातचीत शुरू की। वर्तमान में, सीमा वार्ता और व्यापार संबंधों के विकास को इस अर्थ में अभिसिंचित सौदेबाजी माना जा सकता है कि दोनों पक्ष औपचारिक रूप से मौजूदा सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए सहमत हो गए हैं और द्विपक्षीय व्यापार को 60 बिलियन डॉलर से अधिक के स्तर पर ले गए हैं। साथ ही , सीमा की लंबाई को लेकर असहमति और अरुणाचल प्रदेश के बारे में दावे और कश्मीर में चीनी दबाव छल एवं दुर्ग्राह्य सौदेबाजी की प्रमुखता को दर्शाता है। 1980 के दशक के बाद से चीन-भारत संबंधों में बातचीत और एक्शन दोनों का उदय हुआ। इस मामले में कई दौर की बातचीत के बावजूद, दूसरे पक्ष को व्यस्त रखने के लिए तनाव और अनिश्चितता के स्तर को बनाए रखने की नीति को बनाए रखा गया है ; 1980 के दशक से अब तक का अनुपात उच्च वार्ता ,

व्यापार के मोर्चे पर उच्च कार्रवाई , सीमा निपटान के मामले में कम कार्रवाई, कश्मीर मामलों में चीनी दबाव कारक को आगे बढ़ाने और पाकिस्तान के आर्थिक और राजनयिक विकास में उच्च कार्रवाई को बताता है। लेकिन साथ ही साथ हिमालय और हिंद महासागर क्षेत्रों में चीनी और भारतीय सैन्य क्षमता और नीतियों का निर्माण दर्शाता है कि भारत ने भी चीन को भारत के साथ उलझाए रखने और भारत के वार्ता और एक्शन क्षेत्रों के दृष्टिकोण को बनाने के लिए अनिश्चितता के स्तर को बनाए रखने के लिए चीनी दृष्टिकोण को अपनाया है। यदि चीन की मंशा 1962 में हार के बाद भारत की संधि को सुरक्षित करने की थी और भारत को चीन की अगुवाई वाली दक्षिण एशियाई प्रणाली के अधीनस्थ सदस्य के रूप में एक पद स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, तो भारत के सामने अप्रत्याशित परिणाम आए। इसने चीन की कार्रवाई के विरूद्ध भारतीय राष्ट्रवाद को जगाया और दुनिया के कई तीसरे देशों को चीन के सैन्य हस्तक्षेप में विश्वास के विषय में सचेत किया जिसने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए उसकी प्रतिबद्धता को कलंकित किया। इसने भारत की सामान्य कूटनीतिक नीति के माध्यम से नेहरू की शांति नीति और भारतीय सशस्त्र बलों के विकास के लिए उनके विरोध को अस्वीकार करने का नेतृत्व किया किया। भारत के मुख्य क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी , पाकिस्तान को चीनी सैन्य और परमाणु सहायता, ने एक भावना पैदा की कि उनका उद्देश्य भारत को हिमालयी क्षेत्र के साथ-साथ भारत के पश्चिमी लम्बाई पर सीमित करना है और इसका परिणाम हुआ कि वाशिंगटन और मॉस्को दोनों ने चीन के 1962 के कार्य को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए विनाशकारी कहा था और दोनों ने भारत के सैन्य विकास में सहायता के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया। इस प्रकार, चीन का युद्ध लंबे समय में प्रति-फलदायक था। यदि नीति

का उद्देश्य दुश्मन की घरेलू राजनीति और विदेश नीति को बदलना है , तो भारत में माओ के दस्तक देने के बड़े ही अनपेक्षित परिणाम थे जो चीन के लाभ के लिए नहीं थे और जिसने चीन को भारत के साथ एक बधी हुई स्थिति में छोड़ दिया। 1840 में एक चीनी शासक ने कथितरूप से कहा था किः "लंबे समय तक बातचीत ने बर्बर लोगों को चिंताग्रस्त और थका हुआ बना दिया है,हम अचानक उन पर हमला कर सकते हैं और इस तरह उन्हें वश में कर सकते हैं"। यदि यह इस समय चीन की भारत नीति के लिए एक प्रासंगिक नुस्खा है , तो युद्ध विकल्प को बनाए रखने के लिए बातचीत का एक छद्म रूप आवश्यक है। यह 1860 में प्रिंस गोंग की सलाह को याद करता है: "शांति और मित्रता के लिए रिज़ॉर्ट जब अस्थायी रूप से ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाता है; तो अपनी वास्तविक नीति के रूप में युद्ध और रक्षा का उपयोग करें"।

(ख) चीन की वार्ता की रणनीति के दूसरे रूप को मौजूदा पैंतरेबाजी के साथ चलती हुई 'उपलक्षित वार्ता' कहा जा सकता है। चीन के तीन प्रमुख भौगोलिक और सामरिक पड़ोसियों में कोरिया,ताइवान और वियतनाम के युद्धों और संकटों के लिए चीन के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण तरीके से बातचीत का यह रूप सामने आया है, जहां अमेरिका के साथ संपर्क का एक सतत स्वरूप,एशिया में प्रमुख शक्ति-प्रशांत , उभरा है। कोरियाई युद्ध के बारे में माओवादी सोच के अनुरूप कई परिणाम थे। (क) इसने (अमेरिकी) अहंकारको गिरा दिया , क्योंकि जनरल डोलस मैकआर्थर को भरोसा था कि वह कोरियाई प्रायद्वीप को ताकत से एकजुट कर सकता है और क्षेत्र में अमेरिकी उपस्थिति का विस्तार कर सकता है; (ख) इसने अमेरिकी सैन्य जनरलों को फिर से आश्वस्त किया कि वे प्रत्यक्ष संघर्ष में चीन का सामना न करें ; (ग) यह संयुक्त राज्य अमेरिका को

युद्धविराम समझौते के लिए लाया था ; (घ) यह सुनिश्चित किया कि दोनों कोरिया, कोरियाई एकीकरण के विकल्प के रूप में विभाजित रहेंगे और कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिकी और जापानी वाणिज्यिक और सैन्य प्रभावों की उन्नति की संभावना रहेगी; (ङ) इसने उत्तर कोरिया की सैन्य कार्रवाई को बढ़ावा देने और कोरिया में चीन के युद्ध के प्रयासों में मदद करने के लिए स्टालिन की अनिच्छा को बढ़ावा देने में सोवियत की आक्रामकता को उजागर किया जहाँ से चीन-सोवियत संबंधों में सीमा का पता चला। इस सूची में,युद्धविराम समझौता और युद्ध के कैदियों का प्रत्यावर्तन औपचारिक वार्ता की वस्तुएं थीं जोदोनों ही हासिल हुए। शांति संधि भविष्य की वार्ताओं का विषय था,लेकिन किसी भी पक्ष के पास उस उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहन नहीं था।

1958 का ताइवान संकट एक और उदाहरण है जो दिखाता है कि चीन की कार्रवाइयों में अक्सर कितने मकसद होते हैं। चीन ने गोलाबारी और धमकी देने की पहल की और उसने ताइवान के उद्देश्य से लगातार एक मजबूत सैन्य उपस्थिति बनाए रखी है और अगर वह स्वतंत्रता की घोषणा करता है तो वह ताइवान को बलपूर्वक कब्जाने की सार्वजनिक स्थिति में है। शंघाई कम्यूनिके (1972) के बाद,अमेरिका ने स्वीकार किया कि ताइवान चीन का हिस्सा था लेकिन शांतिपूर्ण तरीकों से एकीकरण को आगे बढ़ाया जाना था। माओ और चाउ के साथ अमेरिकी बातचीत से पता चला है कि बीजिंग ताइवान को पुनर्प्राप्त करने के लिए जल्दी में नहीं था क्योंकि यह वाशिंगटन के साथ एक मजबूत संबंध स्थापित करने और मॉस्को की जांच करने के लिए तीन पावर गेम बनाने का अधिक इच्छुक था। ध्यान दें कि शंघाई कम्यूनिके ने दो अभिसरण हितों का खुलासा किया, अर्थात् ताइवान का शांतिपूर्ण एकीकरण और वाशिंगटन को चीन के पक्ष में लाना। 1961 में चीनी

सेना को गुप्त निर्देशों में (पहले उद्धृत) बीजिंग ने तर्क दिया था कि वह अमेरिका के साथ एक पैकेज डील चाहता था और उसके सैनिकों को ताइवान से हटना चाहिए। शंघाई कम्यूनिके ने दर्शाया कि चीन तब तक आधे उपायों के लिए तैयार था जब तक कि बड़े रणनीतिक लाभ उपलब्ध थे, इस मामले में इसके साथ-साथ मॉस्को और अमेरिका के साथ संपर्कों का निर्माण भी करना चाहता था। यहाँ माओ और चाऊ ने निक्सन और किसिंजर को कठिन समय में न रखने का निर्णय लिया लेकिन बातचीत और कार्रवाई दोनों मंचों को विकसित कर इन्हें ताइवान के प्रश्न में त्रिकोणीय और राजनयिक तरीके से उलझाकर रखने का निर्णय लिया।

1972 के बाद के अमेरिका-चीन-ताइवान संबंध की तुलना करें जो अब 1958 की स्थिति के साथ क्रमिक और स्थिर दोनों के रूप में देखा जाता है। चीन ने कई लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए गोलाबारी का उपयोग किया। यह अमेरिकी नीति की सीमाओं का परीक्षण करना चाहता था। यह ताइवान में उसके स्थायी हितों का दावा करना चाहता था और यह सुनिश्चित करना चाहता था कि यह अमेरिकी क्षेत्र में या स्वतंत्रता में न बहे। यह मरीन को लेबनान भेजने में अपने घमंड के लिए अमेरिका का दरवाजा खटखटाना चाहता था। इसकी नीति अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ाने,अमेरिका को सबक सिखाने और इसे कठिन समय देने की थी। यह चीन और ताइवान के प्रति ख्रुश्चेव की नीति का परीक्षण करना चाहता था। चीन तीसरी दुनिया के देशों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के बारे में बात कर रहा था लेकिन किसिंजर के शब्दों में, यह मास्को और वाशिंगटनके साथ-ही-साथ अभ्यास के उद्देश्य सेजुझारू सह-अस्तित्व के विषय में था। दो मानदंड सामने आए: संघर्ष को सीमित रखना लेकिन विपक्ष को उलझाए रखने के लिए एक बड़ी क्षमता

बनाए रखना। दूरदर्शितामें, 1958 में ताइवान पर संकेतों ने वाशिंगटन और ताइपे के साथ मौन वार्ता को खोलने का संकेत दिया,जिसकी पुष्टि शंघाई कम्युनिक्स में अमेरिका और चीन के बीच शांति बनाए रखने के लिए अभिसरण हितों की अभिव्यक्ति द्वारा की गई थी।

हालांकि,अमेरिका-चीन-ताइवान रिश्तों में कई कारण हैं जो चीन की रणनीति और उसकी कूटनीति को प्रभावित करते हैं। जैसे क्या ताइवान मुख्य समूह में शामिल होगा और किन शर्तों के अधीन ? क्या अमेरिकी कांग्रेस ताइवान नीति अधिनियम में घोषित की गई अपनी नीति को त्याग देगी और ताइवान और ताइवान के लोगों को आत्मरक्षा हथियार और नैतिक समर्थन प्रदान करना बंद कर देगी ? क्या अमेरिकी नौसेना ताइवान जलडमरूमध्य के आसपास के क्षेत्र को चीनी सेना के लिए छोड़ देगी और पश्चिमी प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में चीनी नौसेना की पूर्व-प्रमुखता को स्वीकार करेगी ? क्या अमेरिका-जापान सैन्य दिशानिर्देश,जो वर्तमान में यह कहते हैं कि ताइवान और खुली समुद्री गलियां अमेरिकी और जापानी राष्ट्रीय हितों के लिए महत्वपूर्ण हैं,उनको अमेरिका और जापान के रक्षा क्षेत्र के बाहर ताइवान को बाहर करने के लिए संशोधित किया जाएगा? ये खुले सवाल हैं। उनका अस्तित्व इंगित करता है कि ताइवान मुद्दा एक रणनीतिक चीन-अमेरिका-ताइवान-जापान समीकरण का हिस्सा है जो इसे सभी पक्षों द्वारा एक युद्धाभ्यास के साथ छद्म सौदेबाजी की स्थिति का एक रूप बनाता है।

इन उदाहरणों से पता चलता है कि अपने सामरिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपने राजनयिक साधनों का उपयोग करने के लिए चीन का दृष्टिकोण संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक या एक से अधिक पैकेज डील से हुआ है जो कि एकतरफा लाभ के साथ है। माओवादी

चीन ने 1940 और 1960 के दशक के बीच आधिकारिक घोषणाओं में अमेरिकी साम्राज्यवाद की हार की मांग की थी , लेकिन उस उद्देश्य को कट्टर साम्राज्यवादी के साथ सौदा करने के पक्ष में छोड़ दिया गया था जहां उनके हितों का अभिसरण हुआ था। यह तब हुआ जब दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि वे 1970 के दशक में यूएसएसआर के बिना अपने रणनीतिक हितों का पीछा नहीं कर सके। चीन के राज्य-क्षेत्र में कूटनीति का महत्व भी बढ़ा है। 19 वीं सदी की सोच की तुलना करें जब सम्राट और उनके सलाहकारों ने गौण पश्चिम के साथ कूटनीतिक विमर्श में कोई मूल्य नहीं देखा और बर्बर लोगों को पदच्युत करने के लिए अस्थायी रियायतों की सबसे अच्छी आवश्यकता को मान्यता दी।

वर्तमान में,कूटनीति चीनी राज्य मशीनरी का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसने वैश्विक पहुंच हासिल कर ली है। चीन की राजनयिक मशीनरी का अब राज्य के तंत्र में और राजनीतिक प्रतिष्ठान के रवैये में एक संस्थागत आधार और वैधता है। शाही अतीत में,कूटनीति की भूमिका अनियमित और माध्यमिक थी और इसका उद्देश्य चीनी व्यापारियों के साथ वाणिज्यिक संबंधों को स्थिर करना था। हालांकि,अफीम युद्ध के बाद,पश्चिमी व्यापारियों और सरकारों के पक्ष में संधि बंदरगाहों की स्थापना,हांगकांग की समाप्ति और बीजिंग में निवासी मिशनों की स्वीकृति के कारण,चीन के शासकों ने क्षेत्रीय कूटनीतियों की स्वीकृति सहित ड्यूरस के तहत पश्चिमी कूटनीतिक सिद्धांतों को अपनाने के लिए मजबूर किया। और अतिरिक्त-क्षेत्रीयता जिसने पश्चिमी उपनिवेशवाद के हाथों पीड़ित-हुड और अन्यायपूर्ण संधियों की स्मृति से चीनी मानस को डरा दिया। चीन के प्रमुख और विदेश मंत्री चाउ एनलाई और सैन्य रणनीतिकार माओ के विशेषज्ञ हाथों में चीनी कूटनीति का 1949 के बाद का उद्देश्य शक्ति और कूटनीति द्वारा इन अन्यायपूर्ण

कार्यों के परिणामों को पूर्ववत करना था। तिब्बत और दक्षिण में झिंजियांगऔर उत्तर पूर्व में मंचूरिया और मंगोलिया में चीनी विचार के स्वरूप के संदर्भ में सहारा दिया गया,जिसने विदेशी सीमाओं के खतरों और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों के खतरों पर जोर दिया। ये कार्य मुख्य रूप से चीनी सैन्य कार्रवाइयों पर आधारित थे,लेकिन गैर-चीनी दुनिया को चीन की नीतियों को समझाने के लिए कूटनीति की आवश्यकता थी- जो चाउ एनलाई ने सैन्य कार्रवाई (तिब्बत, कोरिया और ताइवान और चीन-भारतीय सीमा के अनुसार) को सही ठहराने के लिए की थी,विदेशी शक्तियों के साथ अस्थायी या दीर्घकालिक संरेखण बनाने तथा नेपाल,बर्मा के साथ सीमा समझौतों पर बातचीत करने,बांडुंग और भारत-चीन समझौता,और अन्य लोगों (सोवियत रूस , भारत, पाकिस्तान और अन्य राष्ट्र के रूप में दोस्ती और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व समझौतों पर बातचीत करें), चाउ एनलाई के साथचीनी कूटनीति को चीन की रणनीति के दोहरे चरित्र को विकसित करने के लिए अनुगमित किया गया था: अपनी दक्षिणी सीमाओं पर चीन की रणनीतिक उपस्थिति को सहारा देने के लिए जहां एक शक्तिशाली सैन्य और राजनयिक जवाबी बल चीन के हितों को कमजोर करने और शक्ति संतुलन हासिल करने के लिए मौजूद नहीं था उसके लिए इसका उपयोग किया गया था। इसके उत्तरी , पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में जहां जापानी , रूसी और अमेरिकी सत्ता ने 1950 और 1960 के दशक में चीनी हितों को धमकी दी थी। इस परिप्रेक्ष्य में,समकालीन चीनी कूटनीति की नींव माओ-चाउ-एनलाई युग में रखी गई थी। माओ और चाउ के बाद,चीन की कूटनीति इस दोहरे ढांचे में कार्य करती है , और इससे चीन को अवसर और चुनौतियां मिलती हैं, जिन पर हम इस लेख के समाप्ति खंड में चर्चा करेंगे।

चीन की बातचीत की कार्यनीति का श्रंखला समूह

चीन ने बातचीत की कार्यनीतियों की एक समृदध श्रंखला का प्रदर्शन किया है।

(क) जब पश्चिमी दूतों को चीनी दरबार में लाने के लिए दबाव डाला गया,तो दरबारियों ने इस सिद्धांत पर आकर्षक कूटनीति और देरी करने वाली रणनीति का इस्तेमाल किया कि एक व्यक्ति, बर्बरों से आत्मसमर्पण करवा सकता है। आगंतुकों और चीनी अदालत की गरिमा के साथ चीनी शिष्टाचार के बीच एक करीबी संबंध था। इसका उद्देश्य मांग करने वालों के आसपास सांस्कृतिक रेखाएँ खींचना और कूटनीतिक संपर्क जो चीनी अदालत की सांस्कृतिक और लौकिक श्रेष्ठता को कमज़ोर करेगा उसको कम करना था।

(ख) अफीम युद्ध के बाद,पश्चिमी शब्दों की स्वीकृति एक सैन्य हार का परिणाम थी। इन परिस्थितियों में बहस करने के लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि सैन्य हार राजनयिक आत्मसमर्पण के बराबर थी।

(ग) कोरियाई युद्धविराम वार्ताओं में,कम्युनिस्ट चीन की वार्ता रणनीति निम्नलिखित तरीके से सामने आई। चीन के वार्ताकारों ने कार्यसूची आइटम समाहित किया। उनके विचार और निष्कर्ष का क्रम पूर्व निर्धारित था,काश कि अमेरिकी वार्ताकारों ने चीनी एजेंडे को स्वीकार कर लिया होता। चीन के वार्ताकारों के लिएकार्यसूची का वांछित निष्कर्ष था। चीन की रणनीति विफल हो गई क्योंकि अमेरिकी वार्ताकार युद्ध मुद्रा के युद्धविराम और कैदियों के आदान-प्रदान के लिए सहमत हुए और फिर बाहर चले गए। यहां परचीनी शिष्टाचार और गरिमा, जो शाही कूटनीति की विशेषता थी उसे त्याग दिया गया। चीन के मुख्य वार्ताकार ने अमेरिकी वार्ताकार को पूंजीवादी बदमाश , हत्यारे आदि की संज्ञा दी। इस तरह की अशिष्टता माओवादी युग के

प्रारंभिक भाग में एक विशेषता थी,लेकिन यह लंबे समय तक नहीं रही।

(घ) भारत-चीन समझौते में,चीन की आकर्षक कूटनीति लौट आई और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व विषय को निभाया गया।

(ङ) अमेरिका के साथ 1954 से राजदूतों की वार्ता में, 120 से अधिक बैठकों के साथ,संचार का एक औपचारिक क्रम स्थापित किया गया था। ये बिना किसी औपचारिक कार्यसूची के वाद-विवादों से मुक्त थे। इस कार्यसूची में प्रत्येक पक्ष द्वारा एक उद्घाटन वक्तव्य शामिल था जिसमें उनकी रुचि का वर्णन समाहित था और एक प्रारंभिक बहसऔर प्रत्येक पक्ष के पदों की बारीकियों पर चर्चा करने और उनका पता लगाने का अवसर था। यह प्रारूप छद्म सौदेबाजी या/और उपलक्षित पैंतरेबाज़ी के समान हो सकता है। यहाँ तक कि औपचारिक समझौते के बिना भी वे उपयोगी थे क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को जोड़ने के लिए संवाद का एक आधिकारिक चैनल स्थापित कर लिया था और प्रक्रिया और दोनों पक्षों की पेशेवर तरीके से बातचीत करने की इच्छा ने तब बीजिंग की व्यावसायिकता का खुलासा किया जब यह उसके हितों के अनुकूल होती थीं। निहितार्थ यह नहीं है कि मायावी या मौन वार्ता आवश्यक रूप से अभिसरण हितों और समझौतों की ओर ले जाती है,लेकिन यदि राजनीतिक परिस्थितियों के पक्ष में परिस्थितियाँ बदल जाती हैं,तो वे ऐसा कर सकते हैं।

21 वीं सदी की शुरुआत में चीन की बातचीत की रणनीति *शी* या दुनिया की दिशा और क्षेत्रीय स्थिति के उसके अनुमान पर निर्भर करती है लेकिन हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि उसकी 'रणनीतिऔर कूटनीति' की पटरियां अच्छी तरह से एकीकृत नहीं हैं ; दोनों के प्रक्षेपवक्र में अलग-अलग

चालक हैं।कूटनीति के लिए , चालक को वर्तमान में अपने आधुनिकीकरण के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शांतिपूर्ण वातावरण की तलाश करनी है। लेकिन रणनीति के पथ में अलग-अलग ड्राइवर हैं। हम 1800 के दशक से चीनी सोच में बिंदुओं को जोड़ते हैं। प्रिंस डोंग (पहले उद्धृत) ने अपने अधिकारियों को यह याद रखने का निर्देश दिया कि शांति एक अस्थायी अभियान था और युद्ध नीति थी। यह चेतावनी दी गई है कि चीन के नियंत्रण और युद्ध नीति से परे परिस्थितियों से शांति की स्थिति तय होती है जो स्थायी दृष्टिकोण पर आधारित होती है। माओ ने सूर्य त्ज़ु और पूर्वजों की सोच का अनुगमन कियाऔर परिस्थितियों की आवश्यकतानूसार सशस्त्र संघर्ष और शांतिपूर्ण आवास उनका मार्गदर्शक सिद्धांत था। उनका घोषित नियम था कि शत्रु को रणनीतिक रूप से तिरस्कृत किया जाए,लेकिन इसका सम्मान किया जाए। (चीन के साथ काम करने वाले दुश्मन के लिए निहितार्थ यह है कि यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियां होनी चाहिए कि चीन निकट भविष्य में इसका सम्मान करता है।) सैन्य विकास को शामिल करने वाले चार आधुनिकीकरणों को आगे बढ़ाने में,डेंग शियाओपिंग इन आधुनिकीकरणों के बारे में पहले चाउ एनलाई द्वारा स्थापित लाइन का अनुसरण कर रहे थे,लेकिन उन्होंने इसमें निम्नलिखित निर्देश को जोड़ा: “शांति से निरीक्षण करो; हमारी स्थिति को सुरक्षित करें; शांति से मामलों का सामना करें; हमारी क्षमताओं को छिपाएं और हमारे समय को बांधें; कम प्रोफ़ाइल बनाए रखने में अच्छा होगा; और कभी भी नेतृत्व का दावा न करें ”। ये निर्देश काफी विस्तृत हैं, लेकिन वे दुश्मन को हराने के लिए धोखे और आश्चर्यजनक हमले का उपयोग करने के लिए माओ के तरीके के अनुरूप हैं। चीन के दर्ज किए गए व्यवहार में ‘मित्रता’ और ‘शांति’ शत्रुता का प्रबंधन करते हुए और उन्हें सबक सिखाने के लिए ‘बातचीत कार्यसूची’ का एक अनिवार्य हिस्सा है , यह मानक नियम है जो भारत (1962) , वियतनाम (1979), संयुक्त राज्य अमेरिका पर

लागू किया गया है। (कोरियाई युद्ध) और सोवियत संघ (यूसूरीसीमा संघर्ष जिसनेकिसिंजर कैरी रिपोर्ट को जन्म दिया, चीन द्वारा प्रारंभ किए गए थे)। इस तरह 'कार्रवाई कार्यसूची' विभिन्न नियमों का पालन करता है। संस्थागत चालक भी अलग हैं। चीन का विदेश मंत्रालय शांति और सद्भाव मार्ग का चालक है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) और पार्टी नेतृत्व, रणनीति मार्ग का चालक है। जब माहौल कम-गंभीर स्थिति में होता है तो दोनों लाइने समानांतर चलती है लेकिन गंभीर में रणनीति लाइन प्रमुख हो जाती है जैसा कि भारत,वियतनाम,सोवियत संघ और अमेरिका के साथ चीन के युद्ध के मामले में हुआ था।

वर्तमान में,चीन का *'शी* शब्द एशिया में एक प्रवाह की ओर इशारा करता है और दुनिया की स्थिति जो राजनयिक के संस्थागत चैंपियन और चीन के भीतर रणनीति लाइनों के बीच बहस को ट्रिगर करता है को दर्शाता है। संभवतः , चीनी विदेश कार्यालय शांतिपूर्ण आवास रेखा का चैंपियन है,पीएलए रणनीति लाइन का चैंपियन है और पार्टी के नेताओं को दोनों को अवश्य ही संतुलित करना चाहिए। हालांकि,यह एक सरलीकृत कथन है जिसे परीक्षण की आवश्यकता है क्योंकि चीनी निर्णय लेने के कोई आधिकारिक इतिहास नहीं हैं और संकटों में इन संस्थानों या गुटीय समूहों की भूमिका और उप-राजनीतिक समय में उनके कार्यों और सोच को सार्वजनिक रूप से नहीं जाना जाता है। हालांकि,यह विश्वास दिलाया जा सकता है कि कम्युनिस्ट चीन एक युद्धाभ्यास मोड में रहा है , लेकिन अभी भी अंर्त-सरकारी समझौतों के कुछ उदाहरण हैं जो अभिसरण हितों को दर्शाते हैं। लेकिन जारी पैंतरेबाज़ी इंगित करती है कि बीजिंग के निर्णय निर्मातागण एक संतुलन बिंदु पर नहीं पहुंचे हैं जो ज्ञात प्रतिद्वंद्वियों के साथ युद्ध या शांति समझौते का पक्ष लेते हैं। विवाद यह है कि चल रहा युद्धाभ्यास मायावी सौदेबाजी के उपयोग को इंगित करता है जो युद्ध या शांति समझौते से अलग है। मायावी सौदेबाजी

प्रतिद्वंद्वियों को संलग्न करती है और प्रक्रिया-उन्मुख और बातचीत, बातचीत के लिए तथा युद्ध युद्ध के लिए बेहतर होना चाहिए। यह शीर्षतम स्तर पर निर्णय की कमी और चीन के आचरण में आदर्श के रूप में गतिरोध और उप-क्रिटिकल मोड में संबंधों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को इंगित करता है। छद्म सौदेबाजी और युद्धाभ्यास तब प्रबल होता है जब प्रतिद्वंद्वियों के साथ शांति या स्थायी समझौता करने के लिए सामान्य हित मौजूद नहीं होते हैं। प्रतिद्वंद्वियों को नियमित आधार पर संयमित रखने के लिए एक ही समय में छद्म सौदेबाजी उपयोगी है,और वास्तव में आवश्यक है। चीन और उसके पड़ोसियों जापान,उत्तर और दक्षिण कोरिया,ताइवान,दक्षिण पूर्व एशियाई सरकारें,ऑस्ट्रेलिया,म्यांमार,भारत,दक्षिण एशियाई सरकारें इत्यादि के बीच संवादों के प्रसार पर ध्यान दें। इनमें से अधिकांश सभी पक्षों पर छद्म सौदेबाजी की प्रमुखता के संकेत हैं। उसी समय,चीन के सैन्य आधुनिकीकरण और आत्म-रक्षा उद्देश्यों के लिए आक्रामक सैन्य कार्रवाई का उपयोग, चीन ने वियतनाम में अपने कार्यों की व्याख्या करने के लिए जिस सूत्र का उपयोग किया है,उसने चीन के पड़ोसियों के बीच सैन्य संवर्धन को बढ़ाया है। मायावी सौदेबाजी की स्थितियों की संभावना एशियाई राजनयिक परिदृश्य की एक स्थायी विशेषता है जब तक कि चीन और गैर-चीनी मुख्य हितों को शामिल करने वाले गतिरोधी स्थितियों को एक पक्ष के युद्ध और सैन्य हार से या दोनों एक व्यापक शांति समझौते की सहमति से नहीं सुलझाया जाता है।

चीन और उसके पड़ोसियों द्वारा आज एशिया-प्रशांत में सैन्य आधुनिकीकरण को एक खोज के रूप में जायज ठहराया गया है।वर्तमान परिस्थितियों में एक वांछित उद्देश्य,विवादास्पद मुद्दों को गति देने और युद्ध से बचने के लिए, गतिरोध शांति नहीं है,लेकिन यह तुलनात्मक रूप से शांतिपूर्ण है,संकीर्ण रूप से परिभाषित है इसका मतलब युद्ध की अनुपस्थिति है। लेकिन यह चीन और उसके पड़ोसियों के बीच एक अंर्त-राज्य संतुलन के

अस्तित्व का अर्थ ही नहीं है। इस विश्लेषण के अनुसार,21 वीं सदी में चीन युद्धाभ्यास और छद्म सौदेबाजी में उसकी भागीदारी से पहले से ही तब तक परेशान रहेगा,जब तक कि वह उसकी रणनीति और कूटनीति को एकीकृत नहीं करता है जो बदले में चीन के मुख्य चैंपियन-पीएलए,पार्टी के नेताओं और आंतरिक विवादों पर निर्भर करता है। विदेश कार्यालय उन लोगों के साथ जो उनके आर्थिक और सामाजिक आधुनिकीकरण की रक्षा करेंगे। 'बोली-प्रक्रिया के समय' को चीन के नेताओं के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि समय एक रैखिक तरीके से आगे बढ़ता है लेकिन चीन जैसे भौगोलिक पड़ोसी और अन्य प्रमुख शक्तियां ऐतिहासिक यादों से प्रभावित होती हैं और वे कमजोर और असफल नीतियों के प्रत्यावर्ती प्रभाव के प्रति सतर्क हैं।

नवीन चीन की कूटनीति: "नदी पार करने के लिए कंकंड पत्थरों के आस-पास तैयारी की प्रक्रिया"?

1800 के मध्य और माओवादी युग के बीच चीन के राजनयिक आचरण की एक ऐतिहासिक समीक्षा पैंतरेबाजी के निरंतर महत्व को चीन की रणनीति और कूटनीति के दृष्टिकोण के मौलिक सिद्धांत के रूप में दर्शाती है। चीन के लिए, बातचीत के अन्य तरीकों के लिए पैंतरेबाज़ी करना बेहतर है,जैसे कि स्थायी शांति समझौते की मांग करना,जहां दोनों पक्ष रियायतें देते हैं,या सैन्य जीत के माध्यम से निपटान की मांग करते हैं,जहां दुश्मन विजेता की शर्तों से सहमत होता है,या छद्म वार्ता से आंतरिक और बाहरी विचार-विमर्श को बढ़ाता करता है। ये तरीके कंकड़ के चारों ओर टकराने के अलग-अलग तरीके हैं। हालांकि,इन विधियों ने चीन को उसके मूल हितों की संतुष्टि प्रदान नहीं की है जिसमें तिब्बत और शिनजियांग में सीमांत सुरक्षा शामिल है और अमेरिकी कांग्रेस द्वारा जारी विदेशी हस्तक्षेप के बिना अपने दावे की

अंर्तराष्ट्रीय स्वीकृति है जो स्वायत्तता और मानवाधिकारों के सम्मान के लिए तिब्बती आह्वान का समर्थन करती हैऔर यूरोप स्थित पश्चिमी समूह शिनजियांग में मानवाधिकार अभियान का समर्थन करना जारी रखती हैं। मुख्य क्षेत्र के नियंत्रण के लिए ताइवान की वापसी एक और मुख्य हित है। इसमें देरी हुई है। कम्युनिस्ट पार्टी और चीन में एक पार्टी प्रणाली के वर्चस्व को बनाए रखना अभी तक एक और मुख्य हित है जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा निरंतरता में स्वीकार नहीं किया गया है। जुलाई 2009 में वाशिंगटन में चीन-अमेरिका रणनीतिक और आर्थिक वार्ता के पहले दौर में,राष्ट्रीय परामर्शदाता दाई बिंगको ने अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निम्नलिखित बयान दिया:

> यह सुनिश्चित करने के लिए कि द्विपक्षीय [अमेरिका-चीन] संबंध दीर्घकालिक और अच्छी प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे,एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें एक-दूसरे को समर्थन देने,सम्मान और समझने और अपने मूल हितों को बनाए रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रमुख चिंताओं में इसकी बुनियादी प्रणालियों और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुरक्षित रखना,इसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के साथ-साथ इसके निरंतर आर्थिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना शामिल है।

1970 और 1980 के दशक के बाद से एक आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में चीन के उदय के बाद और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में उनकी सक्रिय भागीदारी के बाद,अब सवाल यह है कि क्या चीन अभी भी कंकड़ से जुड़कर समूह बना रहा है या उसे नदी पार करने के उपाय मिल गए हैं?

1970 के दशक की शुरुआत से चीन का आर्थिक और कूटनीतिक रिकॉर्ड उसकी बढ़ती हुई शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में आम सहमति के दृष्टिकोण को सही ठहराता है। विशेष रूप से एशियाई,हिंद महासागर और अफ्रीकी क्षेत्रों में चीन की कूटनीतिक और आर्थिक सक्रियता के बारे में आम सहमति है। संक्षेप में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे जा सकते हैं। सबसे पहले,बीजिंग के लिए निक्सन-किसिंजर यात्रा से अंर्तराष्ट्रीय संबंधों का चीन का अंतर्मुखी दृष्टिकोण समाप्त हो गया और एक आम समस्या (रूस) के साथ,वाशिंगटन और बीजिंग ने अपना शीत युद्ध समाप्त कर दिया। इस शुरुवात ने चीन के विश्वास को तेज कर दिया कि वह अपने सामरिक और राजनयिक असहाय हितों को आगे नहीं बढ़ा सका ;इसे अमेरीका में एक रणनीतिक साझेदार की आवश्यकता थी,जिसके चीन में क्षेत्रीय दावे नहीं थे और जिसके पास गठबंधनों का एक नेटवर्क था जो कि उदाहरणार्थ,एशिया में जापानी सैन्यवाद के खतरे को बढ़ा सकता था। हालांकि,अमेरिका के साथ उद्घाटन ने चीन के मामलों (अमेरिकी सरकार की विभिन्न शाखाओं,चीन के व्यापारियों,हथियारों के नियंत्रकों और शैक्षणिक विशेषज्ञों) में शामिल अमेरिकी हितधारकों के साथ पैंतरेबाज़ी की प्रक्रिया को तेज कर दिया।अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंधों की स्थापना के बाद , बीजिंग के प्रशिक्षुओं ने पाया है कि द्विपक्षीय,क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित 'कंकड़ों' की संख्या बढ़ी है और तिब्बत,झिंजियांग,सीमा के साथ कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं हैं उदाहरणार्थ भारत के साथ,उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम, दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों , उसके नौसेना और अंतरिक्ष विकास और यहां तक कि 'उसके शांतिपूर्ण उदय 'के अर्थ और निहितार्थ के विषयों में विवाद के संबंध में। अतीत में,साम्राज्यवादी चीन पर्याप्तता और सांस्कृतिक श्रेष्ठता की भावना के कारण अंतर्मुखी रुख अपना सकता था। लेकिन अब अंतर्मुखी स्थिति में वापस लौटने का विकल्प भविष्य

में मौजूद नहीं है क्योंकि उसका सामाजिक और आर्थिक विकास वैश्विक अर्थव्यवस्था में सक्रिय और निरंतर भागीदारी पर निर्भर करता है,और उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा एशिया और चीन के क्षेत्रीय पड़ोसियों में प्रमुख शक्तियों को शामिल करने पर निर्भर करती है। ।

दूसरे,हांगकांग (1997) और मकाऊ (1999) की वापसी ने दोनों मामलों में समझौता वार्ता की शक्ति दिखाई है। जबकि ब्रिटेन के साथ युद्धाभ्यास समाप्त हो गया है और दोनों चीनी प्रशासनिक नियंत्रण और संप्रभुता के अधीन हैं, तोचीन की नीति के बारे में हांगकांग की आबादी में व्यापक अशांति है। हांगकांग में 'एक देश दो प्रणालियों ' के दृष्टिकोण का विकास ताइवान में सार्वजनिक और पार्टी के विचारों को प्रभावित करता है। शामिल खिलाड़ियों के प्रसार के कारण ताइवान की वापसी पर पैंतरेबाजी जारी है: ताइवान के लोकतंत्र स्वतंत्रता चाहते हैं और ताइवान का राष्ट्रवाद मौजूद है और हालांकि, केएमटी उन्मुखीकरण के साथ मौजूदा सरकार मुख्यभूमि के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के पक्ष में है फिर भी यह ताइवान की राजनीति में भूमिका अदा कर रहा है। जापान और अमेरिका की स्वयं ताइवान जल-संधि और ताइवान की सुरक्षा में एक घोषित रुचि है और इस कारण से अमेरिका और जापान ने इस क्षेत्र को शामिल करने के लिए अपने सैन्य दिशानिर्देशों का दायरा बढ़ाया है। चीन स्वीकार करता है कि दिशानिर्देश चीन के कार्यसूची (एजेंडे) को जटिल करते हैं ; उनके नेतृत्व को आंतरिक रूप से श्येन के साथ और अमेरिकी कांग्रेस के साथ बाहरी तौर से युद्धाभ्यास करने के लिए मजबूर किया जाता है जो कि ताइवान संबंध अधिनियम के माध्यम से ताइवान को हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है,जो कि ताइवान के लिए अमेरिकी हथियारों की बिक्री का आधार है। यह मूल हित कैसे संतुष्ट होगा?

तीसरा,माओवादियों ने पहली बार 1949 में मॉस्को की ओर झुकाव के बीच वाशिंगटन के बाद द्विपक्षीय संबंधों के निर्माण के माओ के प्रयास को खारिज कर दिया थाऔर फिर चीन-सोवियत संबंध में दरार पड़ने पर ये वाशिंगटन की ओर झुके। निक्सन-माओ हैंडशेक द्वारा,चीन के कौशल ने इसे एक वैश्विक रणनीतिक त्रिकोण के सदस्य के रूप में अपनी स्थिति को आकार देने में मदद की थी। लेकिन त्रिकोण के तीसरे पक्ष के रूप में उसकी रणनीतिक साझेदार का पद यूएसएसआर के विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो गया। चीन-अमेरिका संबंध 1970 के दशक के प्रारंभ में 'रणनीतिक साझेदारों' सेशुरु होकर आगे 'रणनीतिक प्रतिद्वंद्वियों' से होते हुए 'रणनीतिक प्रतिस्पर्धियों' तक बढ़ेऔर अब स्पष्टवादी,रचनात्मक और सहकारी शक्तियों तक पहुँच गए हैं। शीत युद्ध के बाद अमेरिकी राजनीति की गतिशीलता ने चीनी नेताओं को इन पंक्तियों के साथ पैंतरेबाजी करने के लिए दबाव डाला और लेखन के समय (2012) में एशिया को अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय नीति की धुरी बनाने के ओबामा के अभियान से पता चलता है कि दोनों विरोधी या प्रतिस्पर्धी हैं और इस रिश्ते में अविश्वास है। इस वातावरण में,'कंकड़ को पकड़ना'एक चीनी अनिवार्यता है।

जैसा कि शीत युद्ध समाप्त हो गया है, विचारधारा उस स्तर से चीन-अमेरिका और चीन-रूस संबंधों में एक कारक से कम है जैसी यह अतीत में थी, लेकिन प्रमुख शक्तियों और चीन और उसके क्षेत्रीय पड़ोसियों के बीच अविश्वास एक उप-महत्वपूर्ण तरीके से जारी है। इस तरह की स्थिति एशिया में प्रमुख और छोटी शक्तियों की निरंतर पैंतरेबाज़ी का गुण को प्रदर्शित करती है। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा वर्तमान में मौजूद नहीं है और परिणामत: परमाणु और पारंपरिक निरस्त्रीकरण कम आवश्यक है। हालांकि,एशिया में शक्तियों के बीच उप-महत्वपूर्ण अविश्वास के साथ,चीन के पड़ोसियों की गतिशीलता को विकसित करने के लिए परमाणु और पारंपरिक आयुध की

आवश्यकता है,और उन्हें भी चीन के साथ अपने क्षेत्रीय विवादों के स्थायी शांति समझौते को लंबित छद्म सौदेबाजी में भाग लेने की आवश्यकता है।

दुनिया के लिए चीन का व्यवहार कम हो गया है लेकिन विश्व के प्रति उसकी अंतर्मुखता और केंद्रित दृष्टिकोण समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि , लेखक का मानना है कि चीनी घोषणाओं और शैली में बदलाव से पता चलता है कि चीनी कूटनीति और रणनीति संक्रमण में हैं। हिमालयी क्षेत्र (तिब्बत,भारत और पाकिस्तान) में चीन का दृष्टिकोण ऐतिहासिक,भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से उसके दक्षिणी क्षेत्र में उसके मूल हितों के पदानुक्रमित और चीन-केंद्रित विचारों पर जोर देने से कितना परिस्थितियों से प्रभावित है ? या क्या सीमा पर शांति बनाए रखने की इच्छा दूसरे पक्ष के हितों की संवेदनशीलता और स्वीकार्यता को प्रकट करती है ? हाल ही में तब तक, जब तक कि चीन की सरकार पड़ोसी को सबक सिखाने में विश्वास करती थी (भारत,1962; वियतनाम,1979)। चीन की हार्ड लाइन प्रेस,कम्युनिस्ट पेपर ग्लोबल टाइम्स अभी भी 'दक्षिणी तिब्बत' (अरुणाचल प्रदेश) में चीन के दावे के बारे में सबक सिखाने के लिए , इस प्रकार की भाषा का उपयोग करता है। क्या यह आंतरिक पैंतरेबाजी चीन में पीएलएउन्मुख लोगों द्वारा की जा रही है और भारत,चीन के विदेशी कार्यालय और दिल्ली में चीनी दूतावास को लक्षित कर रहे हैं जो सीमा क्षेत्र में सद्भाव और शांति को बढ़ावा देने और व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने की तलाश में हैं ? चीन और उसके पड़ोसियों के बारे में दक्षिण अफ्रीका सागर में प्रतिस्पर्धा करने वाले दावों के बारे में इसी तरह के प्रश्नों से संकेत मिलता है कि चीनी कूटनीति संक्रमण, समाजवाद को बढ़ावा देती हुई व घर में विकास तथा शांति व विदेशों में उसके मूल हितों पर जोर देती है।

चीन के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और चीनी व्यापार के प्रारंभ ने पश्चिमी

और चीनी विद्वानों द्वारा चीनी विदेशी मामलों पर एक समृद्ध और बढ़ते साहित्य का निर्माण किया है। कियान किचेन के 'टेन एपिसोड्स इन चाइना डिप्लोमेसी' (2005) ने व्यावहारिक सीमाओं के साथ चीन की कूटनीति के विकास के बारे में उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान की थी, लेकिन यह काम निश्चित नहीं है। इसने अंर्तराष्ट्रीय समस्याओं से निपटने में एक बड़ा शक्तिशाली दृष्टिकोण अपनाया जो चीन के अधिकारियों के बीच कम शक्तियों और अमेरिका के साथ सह-प्रबंधन दृष्टिकोण के संबंध में चीन-केंद्रित,पदानुक्रमित संबंध दृष्टिकोण के मिश्रण में विश्वास का सुझाव देता है। क्विचेन1988 से 1998 तक चीनी विदेश मंत्री थे और उनके विचार आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में और एक अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक प्रशिक्षु के तौर पर चीन के उदय में एक महत्वपूर्ण चरण का उल्लेख करते हैं। हाल के अन्य कार्य वर्तमान विश्व के कई देशों के साथ अंर्त-सरकारी संबंधों के विकास की व्याख्या करने में सहायक हैं। चीनी विशेषज्ञों के लेखन से चीन के उत्थान और उसके भविष्य के साथ-साथ चुनौतियों में भी एक आत्मविश्वास का भाव दिखता है। नदी को पार करने का मार्ग खोजने के लिए कंकड़ों को 'टटोलने'का विचार झांग बैजिया से आता है,जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के पार्टी इतिहास अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ साथी और उप निदेशक हैं। उनका विश्लेषण संतुलित है और यह उन चुनौतियों को उल्लिखित करता है जो चीन का सामना करती हैं।

मेरी परिकल्पना यह है कि चीन के नेता और विशेषज्ञ अभी भी कंकड़-पत्थर छान रहे हैं,क्योंकि वे फिसलन वाली हैं, अर्थात् कई प्रमुख और छोटी शक्तियां चीन के साथ पैंतरेबाजी कर रही हैं। यहाँ, सामरिक और वाणिज्यिक खेल में कई खिलाड़ियों के प्रवेश से नदी बड़ी हो रही है और नदी कई बार अपना रुख बदल देती है क्योंकि, अन्य शक्तियां अपनी राजनयिक और सैन्य नीतियों को बदल देती हैं,अपने आर्थिक और सैन्य वजन को बढ़ाती

हैं और कुछ अप्रत्याशित विकास चीनी हितों पर दबाव डालते हैं। चीनी निर्णय निर्माताओं और विश्लेषकों के सामने चुनौती तनाव की स्थिति में अढिग रहनाहै और आश्चर्य में नहीं पड़ना है। इसके लिए उनके नेताओं द्वारा निर्णय लेने के आधार के रूप में उच्च गुणवत्ता और समय पर बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। चीन की अपनी गुप्तचर सेवा पर भरोसा करने की परंपरा है और दशकों से खुफिया कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता का एक इतिहास है। लेकिन खुफिया विफलताओं के उदाहरण हैं। हाल के दो मामले इस बात को स्पष्ट करते हैं। एक मामले में,चीन ने गैर-चीनी चिकित्सकों की मजबूत प्रतिक्रिया पर चीन को दक्षिण चीन सागरों के लिए अपने दावे को एक मौलिक हित के रूप में स्वीकार करने पर आश्चर्यचकित किया। सह-प्रबंधन प्रणाली के बजाय यह अमेरिका के साथ कियान किचेन की पुस्तक के अनुसार,एशिया-प्रशांत के उद्भव के रूप में चीन के पड़ोसियों और अमेरिका की नीतियों में धुरी के रूप में सामने आया। चीन और उसके 'मूल हितों'पर राजनयिक और सैन्य दबाव बढ़ा है।एक अन्य मामले में, म्यांमार में सैन्य सरकार ने चीन की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक प्रमुख बांध का निर्माण स्थगित कर दिया। म्यांमार की कार्रवाई ,पश्चिमी राजनयिक और वाणिज्यिक पहल के लिए म्यांमार के आविर्भाव के साथ,अप्रत्याशित थी और चीन-म्यांमार संबंधों के पदानुक्रमित-लेन-देन की प्रकृति में एक सेंध लगाई थी,जिसे बीजिंग 1980 के दशक से बढ़ावा दे रहा था। इन उदाहरणों से पता चलता है कि 1970 के दशक के बाद से चीन का गैर-चीनी दुनिया के साथ राजनयिक संपर्क बढ़ गया है,उसके कूटनीतिक और सैन्य सेवाओं की जानकारी ने खुफिया विफलताओं में योगदान दिया है।

अंत में,चीन की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के भीतर और चीन और गैर-चीनी सरकारों के बीच होने वाले ध्रुवीकरणों का परिणाम, पैंतरेबाजी करने वाले समूहों और चीन और गैर-चीनी शक्तियों के बीच-चीन के

साथ पैंतरेबाजी का लगातार प्रसार हो सकता है। इस मामले में , रणनीति और बातचीत के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण समकालीन चीन की राजनयिक प्रथाओं के अध्ययन के लिए प्रासंगिक है,भले ही स्थितिजन्य और संबंधपरक सेटिंग आज अतीत के लोगों से अलग हैं।

***

समाप्ति टिप्पणी

1. मैंने सी पी फिजराल्ड पर तैयार किया है , *द चाइनिज़ व्यूऑफ देयर प्लेसइन द वर्ल्ड*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस , लंदन, 1965, पृष्ठ 18-19 और51-53.

2. हेनरी किसिंगर देखें ,*चीन पर*,द पेंगुइन प्रेस ,न्यूयॉर्क,2011,पृष्ठ 20-29 (इसके बाद 'किसिंगर ऑन चीन' के रूप में उद्धृत).

3. *चाइनास् नेगोटिएशनएक्सपेरिएंसेसइसइनपेकिंग्स एप्रोच टू नेगोटिएशन : सिलेक्टेडराईटिंग्स*पर लेख का एक उपयोगी संग्रह है सरकारी संचालन समिति के राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय संचालन पर उपसमिति , अमेरिकी सीनेट , अमेरिकी सरकार मुद्रण कार्यालय , वाशिंगटन, 1969 (इसके बाद 'चीन पर अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट' के रूप में उद्धृत; भी, 'किसिंगर ऑन चीन')।

4. चीनी सेना के लिए गुप्त निर्देशों से , अप्रैल1961, 'चीन पर अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट' में उद्धृत,पृष्ठ 76.

5. पूर्वोक्त, पृष्ठ 75.

6. पूर्वोक्त, पृष्ठ 79.

7. डोनाल्ड एस ज़गोरिया द्वारा इसका अच्छी तरह से विश्लेषण किया गया, 'चोइससइनदपोस्टवारवर्ल्ड (2): कन्टेनमेंटएंडचीन', चार्ल्स गाती , एड में, *कैगिंगद बीयर*, बॉब्स-मेरिल कंपनी, न्यूयॉर्क, 1974, पृष्ठ110-111.

8. 'किसिंगर ऑन चीन', पृष्ठ21में उल्लेख किया.

9. किसिंगर कोरियाई युद्ध के रूप में कॉल 'समथिंग मोर दैन ए ड्रॉ '.यह

एक सैन्य शक्ति , एशियाई क्रांति का एक केंद्र के रूप में चीन की स्थापना की, और एक विरोधी कई दशकों के लिए डर और संमान के योग्य. पूर्वोक्त, पृष्ठ 145-146.

10. भारत-चीन संकट 1953-54 के चीनी विचारों के लिए 'यू.एस. कांग्रेसरिपोर्टऑन चीन'में विश्लेषण देखें ,पृष्ठ21-26;किसिंगर का तर्क है कि 1979 साइन-वियतनाम युद्ध 'हाईपॉइंटऑफसिनो-अमेरिकनस्ट्रेटेजिककोऑपरेशनडयूरिंग द ल्डवॉर' था. देखें 'किसिंगर ऑन चीन,' पृष्ठ340.

11. 'यू.एस. कांग्रेसरिपोर्टऑन चीन'में विभिन्न प्रकार की चीनी सौदेबाजी के बारे में विचारों का उल्लेख किया गया है, पृष्ठ68.

12. 'किसिंगर ऑन चीन' पृष्ठ 2, और 186-187.

13. 'यू.एस. कांग्रेसरिपोर्टऑन चीन'पृष्ठ1,में उद्धृत.

14. 'किसिंगर ऑन चीन', पृष्ठ 70,में उद्धृत.

15. पूर्वोक्त, पृष्ठ 172-174,में उद्धृत.

16. 'ग्रोपिंगअराउंडइनद पबब्लस...' वाक्यांश झांग बैजिया ने व्यक्त किया था,"ओवरव्यू: दएवोलुशनऑफचीनडिप्लोमेसीएंडफॉरेनरिलेशन्सइनद एराऑफरिफार्म, 1976-2005"युफानहाओ में ,सी एक्स जॉर्ज वी , और लोवेल डिटमर , संपादक, चैलेंजेजटूचाइनिज़ फॉरेनपॉलिसी : डिप्लोमेसी, ग्लोबलाईजेशन, एंड द नेक्स्टवर्ल्डपॉवरदयूनिवर्सिटी प्रैस ऑफ केन्टुकी, 2009, पृष्ठ 22.जेड बैजिया चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ शोधकर्ता हैं।

17. 'सीनियरचाइनिज़ ऑफिसियलकॉल्स ऑन यूएस टू रेस्पेक्टचाइनाज़ कोरनेशनलइंट्रेस्ट्स'. www.chinaview.cn, 7 जुलाई2009.

18. चीनकेराजनयिकमामलोंपरसाहित्यबढ़रहाहै।हांगकांग, मकाओऔरमुख्यभूमिकेसाथ-साथपश्चिममेंस्थितचीनीविद्वानोंकीभागीदारीउल्लेखनीयहैऔरआजचीनकेआंतरिकआर्थिकविकासऔरआधुनिकीकरणऔरदुनियाकेविभिन्नक्षेत्रोंकेसाथउसकीबढ़तीसैन्यशक्तिऔरकूटनीतिकजुड़ावकेबारेमेंविश्वासप्रकटकरताहै। हाल के कार्यों के एक नमूने के लिए देखें:झांग युलिंग ,राइज़िंग चाइना एंड वर्ल्ड ऑर्डर ,वर्ल्डसाइंटिफिकपब्लिशिंगकंपनी, सिंगापुर, 2010;बेट्स गिल, राइजिंग स्टार : चाइनाज न्यू सिक्योरिटी डिप्लोमेसी , ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन प्रेस , वाशिंगटन डीसी .,2007;सुजियान गुओ और शिपिंग हुआ,न्यूडाइमेंशन्सऑफचाइनिज़फॉरेनपॉलिसी, लेक्सिंगटन बुक्स, न्यूयॉर्क, 2007; औरझिखुन झू , चाइनाज न्यू डिप्लोमेसी : रैशनल, स्ट्रेटेजीजएंडसिग्नीफिकेन्स,'एशगेट पब्लिशिंग कंपनी, यूके,2010.

लेखक के विषय में

डॉ. अशोक कपूर, राजनीति विज्ञान में कनाड़ा के वाटरलू विश्वविद्यालय, ओंटारियों से प्रतिष्ठित सेवामुक्त प्रोफेसर हैं। ये भारतीय राजनीति, भारत और पाकिस्तान में परमाणु-अप्रसार, पाकिस्तान में राजनीतिक संकट, राजनयिक विकास में भारत का रुख, चीन उदय के निहितार्थ तथा हिंद महासागर की राजनीति से संबंधित 15 किताबों के लेखक हैं।वे इजराइल की परमाणु निशस्त्रीकरण अध्ययन समिति, 1980-81 के सदस्य तथा राजनीति विज्ञान विभाग, वाटरलू विश्वविद्यालय, ओंटारियो के विभागाध्यक्ष थे। डॉ. कपूर के नवीनतम प्रमुख कार्यों में इंडिया - *फ्राम रीजनल द वर्ल्ड पावर, इंडिया एण्ड साउथ एशियन स्ट्रैटेजिक ट्रांइएंगल* (2011) शामिल हैं तथा वे *गवर्नमेंट एण्ड पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया* (आगामी 7वें संस्करण) के सह-लेखक भी हैं।लेखक से :

ashok_kapur@hotmail.com पर संपर्क कियाजासकताहै।

विश्व मामलों की भारतीय परिषद्

सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड़, नई दिल्ली-110 001